वर्ष: 7 अंक: 02

16-31 जुलाई, 2026 (नि:शुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

युवा शक्ति

शिक्षा से सामर्थ्य की उड़ान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की युवा शक्ति को सिर्फ साक्षर नहीं, बल्कि कुशल, आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बना रही है। व्यावहारिक ज्ञान, आधुनिक तकनीक और कौशल विकास पर केंद्रित इस नीति ने प्रशस्त किए हैं भारतीय युवाओं के लिए संभावनाओं के नए मार्ग...

हमें फॉलो करें @NISPIBIndia

समुद्र से आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता भारत

वर्ष 2026 का आधा वर्ष बीत गया है। इन 6 महीनों में 'मन की बात' में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की गई है। जून में भी, देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं समुद्र से लेकर आकाश तक भारत को अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना रही हैं। रेडियो पर प्रसारित होने वाले 'मन की बात' कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात की। प्रस्तुत है प्रमुख संपादित अंश...

- **नौ-सेना :** हाल में ही कोलकाता में आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौ-सेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिपों की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है।
- **सुरक्षित और आत्मनिर्भर :** जून में ही डीआरडीओ ने स्वदेशी 'लंबी दूरी की जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल' का सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की प्रयोगशाला और भारतीय उद्योग साझेदार ने मिलकर बनाया है। यानी, आज समुद्र से लेकर आकाश तक भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
- **रोजगार के अवसर :** C-295, विमान 'मेड इन इंडिया' है और इसने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। ऐसे 40 विमान, भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एयरोस्पेस क्षेत्र को नई शक्ति मिल रही है। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय योग दिवस :** इस बार दुनिया में 2,500 से अधिक स्थानों पर योग कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने अनेक स्थानों पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।
- **विश्व योगासन चैम्पियनशिप :** जून महीने में अहमदाबाद में आयोजित 'विश्व योगासन चैम्पियनशिप' में भारत ने 114 पदक जीते जिनमें 102 गोल्ड शामिल हैं। चैम्पियनशिप की पदक तालिका में भारत प्रथम रहा। सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत-बहुत बधाई।
- **'हरगिला आर्मी' :** असम में एक दुर्लभ पक्षी 'हरगिला' पाया जाता है। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही अब गांवों की पहचान बनने लगे हैं। हजारों ग्रामीण महिलाएं 'हरगिला' को बचाने के लिए आगे आईं - आज उन्हें 'हरगिला आर्मी' के नाम से जाना जाता है।
- **प्रतिभा दिखाने का अवसर :** नागालैंड की Women Futsal League हमारी बेटियों को प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। Futsal को indoor football भी कहा जाता है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं।
- **नालंदा विश्वविद्यालय :** हजारों साल पुराना नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रहा है। दो साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवंत किया है।
- **यूनेस्को विश्व धरोहर :** मेघालय का रूट ब्रिज यह बताता है कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की, धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिज को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है।
- **गणपति बप्पा :** प्रयास करें कि घर, सोसायटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो, वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो। वो अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें। ▪

'मन की बात' पूरी सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

न्यू इंडिया
समाचार

वर्षः 7, अंकः 02 | 16-31 जुलाई, 2026

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)

सीनियर डिजाइनर
फूलचंद तिवारी

डिजाइनर
अभय गुप्ता
सत्यम सिंह

13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

न्यू इंडिया समाचार के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

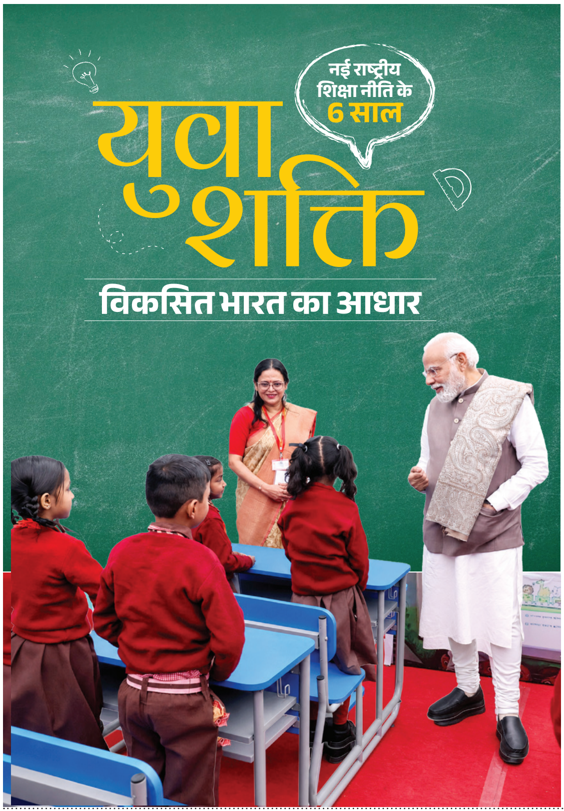

आवरण कथा

6 वर्ष पूर्व 29 जुलाई को आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा तक पहुंच बढ़ी, उच्च शिक्षा का इंफ्रा मजबूत हुआ, कौशल विकास व रोजगार के अवसर बढ़े। शिक्षा नीति से आए बदलाव से अब अमृत पीढ़ी के रूप में युवा बन गए हैं विकसित भारत के सारथी... | 10-21

12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

सबको जोड़ता सबको साथ लाता योग

भारत की हजारों वर्ष पुरानी योग परंपरा आज पूरी दुनिया के लिए बन चुकी है नई उम्मीद | 30-33

समाचार सार | 4-5

व्यक्तित्व : कादम्बिनी गांगुली
भारत में चिकित्सा शिक्षा लेकर प्रैक्टिस करने वाली पहली महिला | 6

'प्रगति' से ऊर्जा, उद्योग और परिवहन को मिली गति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रगति' की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की | 7

नेशन फर्स्ट, भारत का सबसे बड़ा मंत्र
रिपब्लिक समिट-2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित | 8-9

दिल्ली को 6 लेन सुरंग, यूपी को नया हाईवे
केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय | 22-23

भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्वकर्ता बनेगा भारत
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना में 2,400 करोड़ रु. की राशि वितरित | 24-25

बंगाल रचेगा इतिहास... भारत की बढ़ेगी गति
पीएम मोदी ने पीएम-किसान की 23वीं किस्त जारी की | 26-27

प्रवेश-द्वार के रूप में उभर रहा 'ओडिशा'
47,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात | 28-29

पद्म पुरस्कार 2026 : निष्ठा और समर्पण को नमन
विशेष आलेख में देश के 'नायकों' की प्रेरक कहानियां | 34-38

भारत ग्लोबल साउथ की आकांक्षा और अपेक्षाओं की सशक्त आवाज
लगातार 8वीं बार जी-7 में भारत को मिला निमंत्रण | 39-41

भारत और सेशेल्स की दोस्ती के स्वर्णिम 50 वर्ष
सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती पर शामिल हुए पीएम मोदी | 42-43

महिला खेल जगत का स्वर्णिम युग, खेलो इंडिया से वैश्विक मंच तक
एफआईएचः हॉकी महिला नेशंस कप 2026 | 44

प्रकाशकः कंचन प्रसाद, महानिदेशक, सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो)। **पत्राचार और ईमेल के लिए पताः** कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003. **ईमेल- response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812**

संपादक की कलम से...

विकसित भारत : अमृत पीढ़ी का अमृत संकल्प

सादर नमस्कार

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत

अर्थात - उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको।

कठोपनिषद् के इस मंत्र को स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं का जीवन मंत्र बताया था। आज जब भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, तब यह संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाता है।

भारत आज सकारात्मक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। शिक्षा, कौशल विकास, खेल, उद्यमिता और नवाचार हर क्षेत्र में युवा इस बदलाव के सबसे सशक्त वाहक बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश की चार प्रमुख शक्तियों - गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की बात करते हैं, तो उसमें युवा शक्ति को विशेष स्थान प्राप्त है। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है।

'अमृत पीढ़ी' के रूप में पहचाने जाने वाले ये युवा आज केवल भविष्य के सपने नहीं देख रहे, बल्कि विकसित भारत@2047 के सह-निर्माता बनकर उसकी मजबूत नींव रख रहे हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग जैसे मंचों से करोड़ों युवा राष्ट्रीय अभियानों से जुड़ रहे हैं।

बीते 12 वर्षों में भारत सरकार ने युवाओं की क्षमता को पहचानते हुए उन्हें स्टार्टअप, सार्वजनिक सेवा, खेल और रचनात्मक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अभूतपूर्व अवसर दिए हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इसकी बागडोर इन्हीं युवाओं के हाथ में है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी यह बदलाव स्पष्ट दिखता है। अब प्राथमिकता केवल शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस परिवर्तन की मजबूत आधारशिला बनी है। 29 जुलाई 2026 को एनईपी के छह वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यह नीति अमृत पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करते हुए विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को नई दिशा और नई गति दे रही है।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में भारत में चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित पहली महिला कादम्बिनी गांगुली, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, पद्म सम्मान, महिला हॉकी खिलाड़ी और एथलीटों के वैश्विक स्तर पर देश का मान बढ़ाने सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है।

साथ ही, पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैक कवर पर भारतीय नौसेना के तीन आधुनिक जहाज को कमीशन किए जाने पर विशेष सामग्री समाहित है।

आप अपना सुझाव हमें भेजते रहें।

धीरेन्द्र

(धीरेन्द्र ओझा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...

पत्रिका पढ़ने से मिलती है मदद

मैं रूपेश खान, बांकुरा सदर, वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूं। मैं एक पत्रकार हूं और नियमित रूप से न्यू इंडिया समाचार पढ़ता हूं। इससे मुझे काफी मदद मिलती है।

rupeshphoto@gmail.com

सामग्री तथा तकनीक की कसौटी पर उत्कृष्ट

न्यू इंडिया समाचार में सरकार की उपलब्धि तथा भावी योजनाओं को पढ़ना सजग नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य किसी भी पत्र-पत्रिका में यह विवरण उनके नजरिए से पढ़ने को मिलते हैं। मैं स्वयं एक स्वतंत्र लेखक हूं। अतः देश की प्रगति में सूचनाओं की पारदर्शिता के महत्व को समझ सकता हूं। इस महायज्ञ में इस पत्रिका के माध्यम से जो योगदान हो रहा है उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहता हूं।

विवेक रंजन श्रीवास्तव

apaniabhivyakti@gmail.com

पत्रिका से मेरी जानकारी में हुआ काफी सुधार

मैं गुजरात के अहमदाबाद में रहता हूं। मैं गुजरात स्टेट पीसीएस और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। पीआईबी रोज देश के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जरूरी जानकारी देता है। तैयारी में पीआईबी से मिलने वाली जानकारी बहुत अहम भूमिका निभाती है। पिछले कुछ महीनों से मैं गुजराती भाषा में 'न्यू इंडिया समाचार' पत्रिका की डिजिटल कॉपी पढ़ रहा हूं, जिससे मेरी जानकारी में काफी सुधार हुआ है। मेरी तरह कई छात्र पढ़ने के शौकीन हैं। हालांकि मुझे मोबाइल पर डिजिटल कॉपी पढ़ने की बजाय किताब पढ़ना ज्यादा पसंद है।

jaydevsinhdodiya0611@gmail.com

परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार पत्रिका

मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि परीक्षा की तैयारी में मेरे लिए यह पत्रिका बहुत मददगार है।

gavidisravani7@gmail.com

अलग-अलग जानकारी पाने के लिए बहुत काम की है पत्रिका

मैं चंदन बसु एक पत्रिका का संपादक हूं। मेरी उम्र 66 साल है। मुझे नियमित रूप से न्यू इंडिया समाचार ईमेल पर मिलता है। मुझे लगता है कि यह पत्रिका अलग-अलग तरह की जानकारी पाने के लिए बहुत काम की है।

चंदन बसु

outlineofindia@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003

ईमेल- response-nis@pib.gov.in

जहाज पुनर्चक्रण में प्रथम भारत

पुराने, अनुपयोगी या सेवा समाप्त कर चुके जहाजों को तोड़कर उसके दोबारा उपयोग में आने वाले हिस्से को अलग करने के मामले में भारत 2025 में विश्व का सबसे बड़ा शिप रिसाइक्लिंग देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक शिप रिसाइक्लिंग में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2024 के 30.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 35.4 प्रतिशत हो गई है।

इसके साथ भारत ने समुद्री भारत विजन 2030 के शिप रिसाइक्लिंग लक्ष्य को तय समय से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, समुद्री सुधारों और पर्यावरण-अनुकूल जहाज पुनर्चक्रण व्यवस्था को दिया।

स्वदेशी क्रूज मिसाइल का परीक्षण

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 15 जून को ओडिशा तट पर स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी लंबी दूरी की सतह पर हमला करने में सक्षम क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। मिसाइल ने परीक्षण के दौरान सभी निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह शत प्रतिशत स्वदेशी रूप से विकसित क्रूज मिसाइल है, जिसकी सभी प्रमुख उप-प्रणालियां डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं और भारतीय रक्षा उद्योग साझेदारों द्वारा विकसित की गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलआरएलएसीएम के सफल उड़ान परीक्षण पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सभी रक्षा उद्योग साझेदारों को बधाई दी है।

भारत ने छुआ रक्षा उत्पादन का नया शिखर

विकसित भारत 2047 का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भर बनाना, 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देना और भारत में उत्पादन को बढ़ाना है। विकसित भारत 2047 के संकल्प और प्राथमिकताओं में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि शामिल है। ऐसे में रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में लगातार वृद्धि ने आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है।

देवभूमि की लीची इटली तो तेजपुरी लीची दुबई की पसंद

भारत न सिर्फ कृषि को बढ़ावा दे रहा है बल्कि किसानों को सशक्त करने के साथ भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यही वजह है कि देवभूमि उत्तराखंड की प्रीमियम लीची इटली तो असम की जीआई टैग प्राप्त तेजपुरी लीची दुबई के बाजारों में पहुंच रही है। देहरादून की लीची अपनी अनूठी मिठास, आकर्षक लाल रंग, सोंधी सुगंध और बेहतरीन गूदे (पल्प) की गुणवत्ता के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने उत्तराखंड की 1 मीट्रिक टन लीची की पहली खेप इटली भेजने में मदद की। यह यूरोपीय बाजार में न सिर्फ उत्तराखंड की प्रीमियम लीची के प्रवेश बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय फलों की उपस्थिति को मजबूत करेगा।

NAFED ने शुरू की चार पहल... ई-ऑक्शन पोर्टल NAFEX.in लॉन्च

सरकार के सहकारिता से समृद्धि का मंत्र नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैफेड) में भी दिखाई दे रहा है। नैफेड में पारदर्शिता को बढ़ाने और किसानों के कल्याण के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जून के अंतिम पखवाड़े में एक साथ **NAFEX.in**, दृष्टि, ईआरपी और **NAFED** कल्याण पहल की शुरुआत की। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि **NAFEX.in** सहित अन्य पहलें काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वर्ष 2014 में **NAFED** बंद होने की कगार पर था, लेकिन आज सरकार के प्रयासों के कारण नैफेड 30 हजार करोड़ रुपये के टर्नओवर और 500 करोड़ रुपये के मुनाफे के साथ 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है। बीते वर्षों में सरकार ने दलहन, मक्का तथा अन्य उत्पादों की सीधी खरीद के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। सरकार ने नैफेड और एनसीसीएफ को निर्देश दिया है कि अगले दो वर्ष में किसान का पूरा दलहन उत्पाद सीधे खरीदें, बिचौलिये का पूरा तंत्र समाप्त कर किसानों को खाते में उनके पैसे का भुगतान सुनिश्चित करें। नैफेड ने अपने मुनाफे का 1% किसान परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा और करियर विकास के लिए छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है।

गैर-घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति सामान्य, क्षेत्रवार प्रतिबंध हटे

केंद्र सरकार ने उद्योगों और व्यापारियों को राहत देते हुए, गैर-घरेलू कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को पश्चिम एशिया संकट से पहले वाले स्तर को बहाल कर दिया है। इस श्रेणी की एलपीजी आपूर्ति पर लगाए गए सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। साथ ही, संकट के दौरान निलंबित की गई थोक एलपीजी आपूर्ति को भी संकट-पूर्व खपत के 50 प्रतिशत तक बहाल किया गया है। यह फैसला एलपीजी आपूर्ति में हुए सुधार के बाद लिया गया है। एलपीजी उत्पादन और आयातित कार्गो की बेहतर उपलब्धता को देखते हुए एलपीजी पूल में सी3-सी4 स्ट्रीम के परिवर्तन को कम करने का निर्णय लिया है। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित न हो और कुल उत्पादन प्रतिदिन कम से कम 40 टीएमटी बना रहे। तेल विपणन कंपनियों को औद्योगिक एवं वाणिज्यिक ग्राहकों का समग्र डेटा रखने तथा राज्यों को संशोधित व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने पीएनजी के विस्तार और पात्र उपभोक्ताओं को चरणबद्ध रूप से पीएनजी से जोड़ने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। ■

भारत में चिकित्सा शिक्षा लेकर प्रैक्टिस करने वाली पहली महिला

नारी सशक्तीकरण की अनन्य प्रतीक, डॉ. कादम्बिनी गांगुली कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थीं। वह अपनी दृढ इच्छाशक्ति, लगन और समर्पण भाव के परिणामस्वरूप न केवल भारत, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की पहली महिला चिकित्सक बनीं। इतना ही नहीं, उन्होंने कोयला खदानों में काम करने वाली महिलाओं का जीवन सुधारने के लिए भी काफी काम किया। सफल चिकित्सक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रसिद्ध समाज सुधारक डॉ. कादम्बिनी गांगुली विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने का जज्बा रखने वाली करोड़ों महिलाओं के लिए हैं एक आदर्श प्रेरणास्रोत...

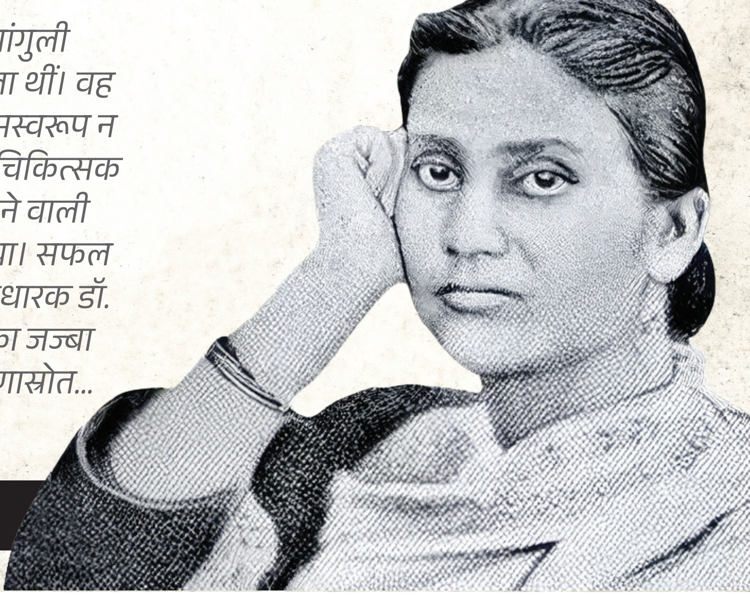

जन्म : 18 जुलाई, 1861 ■ मृत्यु : 3 अक्टूबर, 1923

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कादम्बिनी का जन्म 18 जुलाई 1861 को भागलपुर में हुआ था। गांगुली का स्कूल में दाखिला ऐसे समय में हुआ था जब लड़कियों को शिक्षित करने के बारे में सोचना आम बात नहीं थी। इस अवसर का उन्होंने भरपूर लाभ उठाया और 1883 में वह भारतीय ब्रिटिश राज में स्नातक करने वाली पहली महिला बनीं। कादम्बिनी ने भारत में महिलाओं को घर से बाहर निकलकर नौकरी करने और खुद पर निर्भर होने के लिए काफी प्रेरित किया।

स्नातक के तुरंत बाद उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए काम करने वाले प्रोफेसर द्वारकानाथ गांगुली से शादी कर ली जिन्होंने उन्हें मेडिकल डिग्री लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कादम्बिनी गांगुली ने तमाम बाधाओं के बावजूद अपने क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि प्राप्त की। शुरुआती असफलताओं के बाद आखिरकार उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और साल 1886 में एक बार फिर इतिहास बनाया।

उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और भारत में शिक्षित डॉक्टर बनने वाली पहली महिला बन गईं। इसके बाद वे विदेश गईं। ग्लासगो और एडिनबर्ग विश्वविद्यालयों से चिकित्सा की उच्च डिग्रियां प्राप्त कीं। उन्होंने ब्रिटेन में काम एवं अध्ययन करते हुए स्त्री रोग में विशेषज्ञता हासिल की। साथ ही, उन्होंने तीन अतिरिक्त प्रमाणपत्र अर्जित किए। इसके बाद 1890 के दशक में वो भारत लौट आईं और निजी तौर पर प्रैक्टिस करने लगीं।

कादम्बिनी गांगुली मेडिकल सेवा के साथ महिलाओं के अधिकार की मांग को लेकर भी सक्रिय रही। उन्होंने छह अन्य लोगों के साथ मिलकर 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला प्रतिनिधिमंडल बनाया था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनमें देशभक्ति की भावना जगाने में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं की भूमिका रही। एक डॉक्टर और आठ बच्चों की मां के रूप में कादम्बिनी का व्यस्त जीवन अपने भारत के महिला अधिकार आंदोलन में भूमिका निभाने से रोक नहीं सका।

कादम्बिनी हमेशा महिलाओं की स्वतंत्रता पर उस समय जोर देती रहीं जब बाल विवाह और सती जैसी प्रथाएं समाज में मौजूद थीं। उन्होंने समाज सुधार आंदोलनों में सक्रियता से भागीदारी की। वह कई अन्य आंदोलनों में भी काफी सक्रिय रही। उन्होंने कोयला खदान की महिला खनिकों के लिए काम किया। 1898 में पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अंतिम समय तक कोलकाता में चिकित्सक के तौर पर काम किया। 3 अक्टूबर 1923 को उनका निधन हो गया। ■

'प्रगति' ऊर्जा, उद्योग और परिवहन को मिली गति

बुनियादी ढांचे में गति, तकनीक से जन-कल्याण और सुरक्षित डिजिटल भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रगति' की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 30 हजार करोड़ रुपये की चार बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। अब तक प्रगति मंच पर 85 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है। बैठक में पीएम गतिशक्ति पोर्टल को अपडेट रखने, स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के उपयोग और साइबर ठगी के खिलाफ 'ई-जीरो एफआईआर' व्यवस्था लागू करने पर दिया गया विशेष जोर...

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार विभिन्न राज्यों में फैली चार महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया। लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की संयुक्त लागत वाली ये परियोजनाएं सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संपर्क, औद्योगिक प्रगति और जन कल्याण की दृष्टि से इन परियोजनाओं को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समीक्षा के दौरान एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, समय सीमा के अनुपालन और धरातल पर आ रही समस्याओं के त्वरित निवारण पर विशेष ध्यान दिया गया।

पीएम मोदी ने कहा कि परियोजनाओं में होने वाली देरी न केवल उनकी निर्माण लागत को बढ़ा देती है, बल्कि देश की जनता और उद्योगों को उनके समय पर मिलने वाले लाभों से भी वंचित कर देती है। इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे सभी लंबित मुद्दों का 'मिशन मोड' में समाधान करें।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का प्रभावी उपयोग

प्रधानमंत्री ने 'पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' के उपयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने परियोजनाओं के विवरण, उपयोगिताओं, अवसंरचना परतों, स्वीकृतियों और अन्य क्षेत्रीय सूचनाओं को पोर्टल पर नियमित एवं समय पर अपडेट करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

टीबी मुक्त भारत अभियान में एआई तकनीक

स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 'टीबी मुक्त भारत अभियान' की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। इस बीमारी से उन्मूलन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर विशेष बल दिया। एनसीसी कैडेटों और 'माय भारत' स्वयंसेवकों की एक विशेष टीम गठित करने का भी सुझाव दिया गया है।

साइबर अपराध के खिलाफ सख्त रुख

वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए साइबर अपराध और 'डिजिटल गिरफ्तारी' से संबंधित शिकायतों की भी गंभीरता से समीक्षा की गई। डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सभी संबंधित सुरक्षा और प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा समन्वित, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए।

साइबर धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए स्पष्ट जवाबदेही, त्वरित प्रतिक्रिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों व डिजिटल मंचों के बीच एक सुदृढ़ समन्वय प्रणाली स्थापित करने की बात कही गई है। सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित पंजीकरण और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए 'ई-जीरो एफआईआर' व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने की दिशा में तेजी से कार्य करें।

नेशन फर्स्ट
भारत का सबसे बड़ा मंत्र

भारत न केवल तेजी से बढ़ती हुई बल्कि एक भरोसेमंद अर्थव्यवस्था भी है। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण भारत में निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ है, जिसका बड़े पैमाने पर सकारात्मक असर दिख रहा है। ऐसे दौर में रिपब्लिक समिट-2026 में 'ग्रेट पावर इंडिया : नेशन फर्स्ट' विषय पर चर्चा आयोजित की गई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित...

राष्ट्र सर्वोपरि की भावना ही पिछले एक दशक में भारत की उपलब्धियों और भरोसेमंद शक्ति के रूप में उभरने का मुख्य आधार रही है। भारत का उदय भरोसा, स्थिरता और व्यापक वैश्विक भलाई पर टिका हुआ है। यही वजह है कि भारत न केवल तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है बल्कि एक विश्वसनीय और भरोसेमंद साझेदार के तौर पर भी सामने आया है।

जी-7 समिट में अपनी भागीदारी को याद करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर के नेता 'राष्ट्र प्रथम' के सिद्धांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मानते हैं। सरकार के 12 वर्षों के कामकाज पर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ

कर-मुक्त आय की सीमा बढ़ाई गई

मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचाने के मकसद से आर्थिक सुधार किए गए। इसी कड़ी में कर-मुक्त आय की सीमा बढ़ी है। लोगों की खर्च करने लायक आय में बढ़ोतरी हुई है। तकनीक आधारित ऑनलाइन फाइलिंग व्यवस्था और फेसलेस असेसमेंट मैकेनिज्म जैसे सुधारों के जरिए कर व्यवस्था को आसान बनाया गया है।

विकास यात्रा ने बढ़ाई उम्मीद

भारत की विकास यात्रा ने बढ़ती उम्मीदों का माहौल बनाया है, जिसमें लोग बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, त्वरित सेवाएं और जीवन का बेहतर स्तर चाहते हैं। ये उम्मीदें देश के भविष्य में भरोसे के सकारात्मक संकेत हैं और नागरिकों का यह विश्वास दिखाता है कि तरक्की मुमकिन है।

जीएसटी रिफॉर्म के कारण भी मिडिल क्लास को बहुत सुविधा हुई है। टैक्स फाइलिंग का समय और खर्चा भी बच गया है, क्योंकि यह बहुत ही आसान हो गया है। घर बैठे ही आईटीआर फाइल हो रहे हैं, अगर कोई सेटलमेंट का इश्यू है, तो वो फेसलेस हो रहा है।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

नए मौकों का फायदा

तेजी से बदलते वैश्विक माहौल में नए मौकों का फायदा उठाने में भारत के युवा, उद्यमी, इनोवेटर और स्टार्टअप सबसे आगे हैं। 'राष्ट्र प्रथम' के सिद्धांत पर चलते हुए सुधार, नवाचार और नागरिकों पर केंद्रित शासन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

भारत, मेक इन इंडिया, खादी को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों के अभियान जैसी बड़ी राष्ट्रीय पहल इसलिए सफल हुईं क्योंकि नागरिकों ने 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को अपनाया। जो इलाके कभी हिंसा और पिछड़ेपन से जूझ रहे थे, वहां अब विकास के काम हो रहे हैं। 'बस्तर ओलंपिक' की बढ़ती सफलता इस बात का सबूत है कि इस इलाके में कभी जो डर और अनिश्चितता थी, उसकी जगह अब युवाओं की उम्मीदों और हुनर ने ले ली है।

देश निराशा के दौर से निकलकर आत्मविश्वास और अवसरों के दौर में आ गया है। 'बदलाव मुमकिन है' का भरोसा भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गया है। आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ने देश के कुछ सबसे पिछड़े इलाकों को विकास का इंजन बना दिया है। इन कोशिशों ने लाखों नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। विकास का फायदा सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित नहीं रहता जिन्हें सीधे लाभ मिलता है, बल्कि इससे पूरे समाज की समृद्धि में भी योगदान मिलता है। हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने और एक बड़े नए मध्यम वर्ग के उभरने से आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिली है।

केंद्र सरकार बदलाव के सफर में लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। देश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। यह गति आने वाले समय में और मजबूत होती जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयासों और आकांक्षाओं से 'विकसित भारत' का सपना साकार होगा।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

नई राष्ट्रीय
शिक्षा नीति के
6 साल

युवा शक्ति

विकसित भारत का आधार

श्रियः प्रदुग्धे विपदो रुणद्धि, यशांसि सूते मलिनं प्रमार्ष्टि।
संस्कारशौचेन परं पुनीते, शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधेनुः ॥

अर्थात्, शिक्षा केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सशक्त माध्यम भी है। यही वो अनमोल पूंजी है, जिसके जरिए आज युवा शक्ति हर क्षेत्र में नए-नए कीर्तिमान बनाकर देश का नाम रोशन कर रही है। इस सोच को संकल्प बनाकर भारत के नवनिर्माण की ओर अग्रसर केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों में शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और जनभागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवा केंद्रित पहल शुरू की। इसी का परिणाम है कि 6 वर्ष पूर्व 29 जुलाई को तीन दशक बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से शिक्षा तक पहुंच बढ़ी, उच्च शिक्षा का इंफ्रा मजबूत हुआ, कौशल विकास व रोजगार के अवसर बढ़े। स्टार्टअप तंत्र, डिजिटल प्लेटफॉर्म, समावेशी सोच और भागीदारी के माध्यम से युवा अब अमृत पीढ़ी के रूप में बन गए हैं विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के सारथी...

भारत का जन भी युवा है,
और भारत का मन भी युवा है।
भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है,
भारत अपने सपनों से भी युवा है।
भारत अपने चिंतन से भी युवा है,
भारत अपनी चेतना से भी युवा है।

इन्हीं विशेषताओं के कारण आज दुनिया भारत को एक आशा और विश्वास की दृष्टि से देखती है। भारत युवा है क्योंकि भारत की दृष्टि ने हमेशा आधुनिकता को स्वीकार किया है, भारत के दर्शन ने परिवर्तन को अंगीकार किया है। जन-जन से जग की यात्रा हो या सेवा-समर्पण का मार्ग, परिवर्तन की दिशा हो या पराक्रम का परिचय, सहयोग हो या सुधार, भारत के युवाओं ने अपनी नई पहचान बनाई है क्योंकि उनका लक्ष्य अब आसमां है जो 'कैन डू स्पिरिट' और 'विल डू अप्रोच' में विश्वास रखता है। इस दृष्टिकोण से आज राष्ट्र नए अवसर दे रहा है। 29 जुलाई 2020 को देश के सामने आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य भारत को ज्ञान का ग्लोबल हब बनाना है। इसके साथ ही राष्ट्रीय युवा नीति के जरिए युवाओं को अमृत काल की ओर ले जाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसके तहत युवाओं को आधुनिक कौशल और डिजिटल तकनीक से जोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ देश में स्टार्टअप से लेकर यूनिकॉर्न बनाने की संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। यही नहीं, सेना सहित अन्य क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं, रोजगार-स्वरोजगार की पहलों को जमीन पर उतारा जा रहा है। खेलों को करियर से जोड़कर समाज की सोच को बदलने का एक बड़ा अभियान चल रहा है। अमृत पीढ़ी के रूप में संदर्भित युवा शक्ति भारत की विकास यात्रा की प्रेरक शक्ति बन गई है जो आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ अमृत काल में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अगर कोई सरकार सुधारवादी कदम उठाती है तो युवा परिणाम लाते हैं। सरकार और युवाओं के बीच यह पार्टनरशिप देश के संकल्पों को नई उड़ान दे रही है।

शिक्षा का ग्लोबल हब बन रहा भारत

एक देश पूरे विश्व में अपनी शिक्षा और शिक्षा नीतियों के कारण पहचाना जाता है। केंद्र सरकार ने विश्व स्तरीय शिक्षा का सृजन

शिक्षा के प्रति बदला नजरिया...

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो रही सुनिश्चित

बीते 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने शिक्षा के लिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी है, तो इसी कड़ी में तीन दशक बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। शिक्षा की नींव के तौर पर स्कूली शिक्षा को एनईपी के अनुरूप प्री-प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक आधुनिक रूप दिया है। एनईपी 2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है जिसकी शुरुआत को 6 वर्ष पूर्ण हो गए और अब 7वें वर्ष में कर रही है प्रवेश...

दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल व्यवस्था और दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क

24.69 करोड़ छात्र

14.71 लाख स्कूल

1.01 करोड़ से अधिक अध्यापक

दुनिया में **चौथे स्थान** पर QS रैंकिंग 2026 प्रतिनिधित्व में

उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन

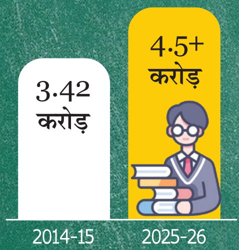

- 1.49+ लाख स्कूलों को आईसीटी और डिजिटल पहल के दायरे में लाया गया।
- 1.76+ लाख स्मार्ट क्लासरूम को मंजूरी।
- 1.79 लाख आईसीटी प्रयोगशालाओं को मंजूरी, वर्ष 2025-26 तक।

उच्च शिक्षा संस्थान तक पहुंच हुई आसान

संस्थान	2014	2025	वृद्धि (%)
आईआईटी	16	23	44
आईआईएम	13	22	69
एम्स	7	23	228
आईआईआईटी	9	25	178
IISER	5	7	40
यूनिवर्सिटी	760	1330	75
कॉलेज	38,500	52,000	35
मेडिकल कॉलेज	431	818	93
एमबीबीएस सीट	51,348	1,28,926	151
मेडिकल पीजी सीट	31,185	85,822	175

> विश्व ने इस बात को माना है कि आज भारत के पास दो असीम शक्तियां हैं- एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है, उसके सामर्थ्य को उतना ही बड़ा और संभावनाओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। लेकिन भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी हैं, उनका डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी अतुलनीय है। भारत अपने युवाओं को डेवलपमेंट ड्राइवर भी मानता है।
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

किया है, जिससे देश का युवा सशक्त बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 6 वर्ष पूर्व बेहतर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए। इसमें अब अंग्रेजी भाषा की बाध्यता नहीं है। शिक्षा की पहुंच ही नहीं, अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का संकल्प बन गया है। इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राइमरी और उच्च शिक्षा के स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई हो रही है। इंजीनियरिंग और आईटी जैसे तकनीकी विषय अब पांच क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़े जा सकते हैं। इससे न सिर्फ पंजीकरण बढ़ेगा बल्कि वैश्विक सोच के साथ स्थानीय समस्याओं के समाधान की क्षमता भी छात्र-छात्राओं में बढ़ेगी।

युवाओं से समृद्ध हर देश में तीन चीजें बहुत मायने रखती हैं, जो युवा की सच्ची पहचान बन जाती है। पहली चीज है- आइडियाज और इनोवेशन। दूसरी है- जोखिम लेने का जज्बा और तीसरी है- कैन डू स्पिरिट यानी किसी भी काम को पूरा करने की जिद। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों - जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो अभूतपूर्व परिणाम मिलते हैं। इसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। यही कारण है कि लगभग

आवासीय स्कूलों ने शिक्षा तक पहुंच आसान की...

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी)।
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी)।
- पीएम-जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) में आदिवासी समुदाय के लिए हॉस्टल सुविधा।

499 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में

1.56 लाख छात्र नामांकित

तकनीक और नवाचार से भविष्य के लिए तैयार होते युवा

6+ करोड़ युवा कौशल विकास पहल के माध्यम से प्रशिक्षित

1.6+ करोड़ युवा पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित

2.19+ करोड़ पंजीकरण MyBharat पोर्टल पर

1+ करोड़ छात्र अटल टिकरिंग लैब में प्रशिक्षित

- उभरती तकनीकों में 16+ लाख परियोजनाओं के विकास में मदद मिली

- 6.4+ करोड़ लोग पीएमजीदिशा के तहत प्रशिक्षित।
- 6.1 करोड़ से अधिक नामांकन डिजिटल स्वयं प्लेटफॉर्म पर हुए, यहां 18,580 पाठ्यक्रम उपलब्ध।
- 3.66 लाख से अधिक ई-कंटेंट संसाधन दीक्षा में 135 भाषाओं में उपलब्ध।
- स्वयंप्रभा, पीएम ई-विद्या और दीक्षा टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल कंटेंट और ई-संसाधनों के जरिए सीखने के अवसरों को और बढ़ाया है।
- 7,400 से अधिक संस्थानों ने उच्च शिक्षा के स्तर पर 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' पहल से अकादमिक और शोध संसाधनों तक पहुंच बढ़ाई है, इसकी लाभार्थी संख्या 1 करोड़ के करीब है।

तीन दशक के इंतजार के बाद 29 जुलाई 2020 को भारत को एक ऐसी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली, जो भारत को ज्ञान का वैश्विक केंद्र बनाने की ओर बढ़ चली है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाना है ताकि भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदल कर अद्वितीय क्षमताओं का विकास किया जा सके। व्यापक मंथन से तैयार हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैज्ञानिक सोच पर आधारित है, ताकि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव न हो। इसी मकसद से बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव किया गया तो शोध को ज्यादा महत्व देकर उसे गांवों तक पहुंचाना अनिवार्य किया गया। यही नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी अब शिक्षा मंत्रालय कहलाने लगा। प्रधानमंत्री मोदी की छात्र-हितैषी नीतियों से देश में बड़े बदलाव आए हैं। इसके तहत एम्स, आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है।

आज भारत, दुनिया की सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में से एक है। देश में 14.71 लाख स्कूल हैं, जिनमें लगभग 25 करोड़ छात्र पढ़ते हैं और 1 करोड़ से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए भी उच्च शिक्षा से जुड़े मूलभूत ढांचे का रणनीतिक विस्तार किया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में नामांकन की दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

एनईपी 2020 ने किया सीखने में सुधार... बेहतर हुई शैक्षणिक यात्रा

170
विश्वविद्यालयों ने अपनाया नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ), जो छात्रों को क्रेडिट जमा करने की सुविधा देता है।

2,469
संस्थान एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) के साथ जुड़े, 32 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट आईडी जारी।

15.48 करोड़ से ज्यादा वेरिफाइड ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी 31 मार्च, 2026 तक बनाए गए।

153
विश्वविद्यालय अब साल में दो बार एडमिशन और कई एंट्री/एक्जिट पॉइंट की सुविधा देते हैं, यह 2035 तक उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पहली बार आम नागरिकों के सुझाव से तैयार हुई नीति...

आजाद भारत में 1968 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना की गई। इसमें शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण कर 10+2+3 पद्धति पर जोर दिया गया। 1952 में लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो 2020 तक चल रही थी। 1986 की शिक्षा नीति में कुछ संशोधन 1992 में भी किए गए। इसके बाद टीएसआर सुब्रमण्यम और फिर जून 2017 में इसरो प्रमुख रहे डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति ने मई 2019 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा' प्रस्तुत किया था। जिसे 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक, 676 जिलों से लगभग 2 लाख सुझावों को शामिल किया गया है। इसके लिए 2015 में भागीदारी परामर्श प्रक्रिया शुरू हुई।

शिक्षा क्षेत्र में बदलाव के लिए बनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी में तेजी से बदलाव लाने वाला कदम बन गया है। इसी का परिणाम है कि आज भारत का युवा देश के सामने आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना कर रहा है। उसका समाधान निकालकर अपनी ताकत साबित कर रहा है। देश के महान शिक्षाविद् और संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सभी की पहुंच में हो, सभी के लिए सुलभ हो। यह

बदलाव का दौर...
रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाले तक

2014

सीमित उद्यमशीलता इकोसिस्टम

350 स्टार्टअप

4 यूनिकॉर्न

- स्टार्टअप में पहचान और नीतिगत समर्थन में कमी, फंडिंग और इनक्यूबेशन और अवसर सीमित, उद्यमिता को एक जोखिम भरा करियर माना जाता था।

2026

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप-यूनिकॉर्न इकोसिस्टम

स्टार्टअप 2.3+ लाख

यूनिकॉर्न 127

21 लाख से अधिक नौकरियां स्टार्टअप में दी गई बीते 12 वर्षों में।

देशव्यापी नवाचार इकोसिस्टम

स्टार्टअप इंडिया और फंड ऑफ फंड्स से उद्यमिता को बढ़ावा, अटल टिंकरिंग लैब से नवाचार संस्कृति को विस्तार, जन विश्वास अधिनियम से अनुपालन बोझ में कमी, अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों से करीब 200 स्पेस स्टार्टअप को बढ़ावा मिला।

शिक्षा नीति, उनके इस विचार को भी समर्पित है। यह शिक्षा नीति, नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर बल देती है। यानी एक प्रकार से यह मानसिकता और अप्रोच में ही रिफॉर्म लाने का प्रयास है। शिक्षा के साथ-साथ युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष अवसर मिले, इसके लिए भी समग्र सोच के साथ केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

कौशल मिशन से कुशल हो रहा नया भारत

युवाओं को उनकी शिक्षा, कौशल और अपेक्षाओं के अनुरूप रोजगार मिले, यह केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। देश के अंदर रोजगार कितना बढ़ रहा है, ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सूचकांकों के जरिए पता चलता है। मजबूत आर्थिक नीतियों से लाखों रोजगार पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत लोगों को कौशल युक्त किया जा रहा है। सरकार के इन प्रयासों से कितने ही नए सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। देश में स्वरोजगार के मौके भी लगातार बढ़ रहे हैं जो केंद्र सरकार में युवाओं के भरोसे को दिखाता है। युवाओं को भविष्य के अनुरूप तैयार करने के लिए, उन्हें लगातार कुशल बनाने, पुनःकुशल बनाने और उनका कौशल निर्माण करने की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ भारत में कौशल मैपिंग का कार्य चल रहा है। भारत के युवाओं के पास अलग-अलग सेक्टर में काम करने का कौशल होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए देश में उच्च शिक्षा संस्थानों, कौशल विकास संस्थानों का भी युद्धस्तर

खेलो इंडिया से संवर रहा **भारत का खेल भविष्य**

- प्रशिक्षण, उपकरण, खेल विज्ञान और वित्तीय सहायता ने एथलीटों के विकास को मजबूत किया है। खेल अब एक सम्मानित पेशे के रूप में उभर रहा है। भारत का लक्ष्य अब केवल भाग लेना नहीं, बल्कि जीतना है।
- 23.68 करोड़ से ज्यादा लोग 'फिट इंडिया फ्रीडम रन', 'फिट इंडिया स्कूल वीक' और 'फिट इंडिया क्विज' में शामिल हुए।

4.5 लाख से ज्यादा स्कूल 'फिट इंडिया स्कूल फ्लैग' से सम्मानित

वैश्विक मंच पर परचम लहराता भारत

30,752 खेलो इंडिया के तहत समर्थित एथलीट

एशियाई खेलों में रिकॉर्ड पदक **107**

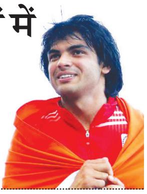

पेरिस पैरालंपिक में **29** पदक

इंफाल-मणिपुर में 2018 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय

पर निर्माण हो रहा है। साथ ही साल 2014 से 2026 के बीच हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम तैयार हुआ है। पिछले 12 वर्षों में विश्वविद्यालय और कॉलेज खुलने की संख्या लगातार बढ़ी है। कॉलेज बढ़ने से स्वाभाविक तौर पर सीटों की संख्या भी बढ़ी है, युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़े हैं। कौशल विकास की विभिन्न योजनाओं के तहत देश में 6 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

खेल अब करियर की नई पहचान

युवाओं को हर क्षेत्र में मिल रहे नए अवसरों की बदौलत पिछले 12 वर्षों में भारतीय खेलों का एक नया युग शुरू हुआ है। यह नया दौर भारत को सिर्फ एक बड़ी खेल शक्ति बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेलों के जरिए पूरे समाज को मजबूत और सशक्त बनाने का एक बड़ा अभियान है। एक समय था जब देश में खेलों को लेकर उदासीनता का भाव था। स्पोर्ट्स भी एक करियर हो सकता है, ये कम ही लोग सोचते थे। इसकी वजह थी कि स्पोर्ट्स को सरकारों से जितना समर्थन और सहयोग मिलना चाहिए था, वो मिलता नहीं था। इसलिए गरीब, मध्यम वर्ग और गांव-देहात के बच्चों के लिए खेल में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल था। ज्यादातर माता-पिता को भी लगने लगा कि बच्चे को उस प्रोफेशन में जाना चाहिए जिससे उसका जीवन व्यवस्थित हो जाए लेकिन अब समाज के दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए खेल को एक

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

57.7 करोड़
लोन स्वीकृत में 40+ लाख करोड़ रुपये की राशि लॉन्च से अब तक स्वीकृत

लोन की संख्या में 28% वृद्धि

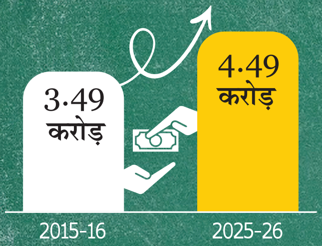

लोन की राशि में 312%वृद्धि

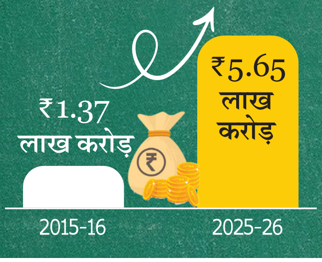

रोजगार के अवसरों तक तेज पहुंच

12.5 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र

19 रोजगार मेलों के माध्यम से जारी

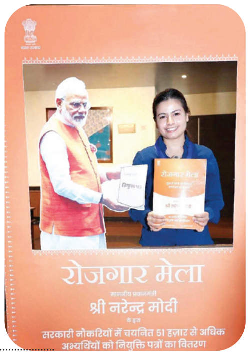

- 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने में मदद करने के उद्देश्य से अगस्त, 2025 में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरु की गई। इस योजना पर सरकार 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।
- 3.43 करोड़ से अधिक नौकरियां 2025-26 में नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई। यह पोर्टल डिजिटल रोजगार बाजार के तौर पर काम करता है।

1.5 लाख युवाओं को सेना में अग्निवीर योजना के तहत शामिल किया जा चुका है।

भारत ने जंजीबार और आबू धाबी में दो अंतरराष्ट्रीय आईआईटी कैंपस खोले हैं तो आईआईएम अहमदाबाद ने भी दुबई में अपना कैंपस खोला है। उम्मीद है कि 15 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर खोलेंगी।

आकर्षक पेशे के तौर पर देखा जाने लगा है। इसमें खेलो इंडिया अभियान ने बड़ी भूमिका निभाई है।

पीएम मोदी की कोशिशों से देश के लोगों की सोच में बदलाव आया। केंद्र सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई जिससे खेलों में करियर बनाने के रास्ते खुले। परिणाम हुआ कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीत कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पेरिस ओलंपिक में भी भारत ने 6 पदक जीते। टोक्यो पैरालंपिक्स में भी भारत के खाते में 19 पदक आए। इसी तरह पेरिस पैरालंपिक्स में भारत ने 29 पदक जीते। नए भारत का मंत्र है-जुट जाओ और जीतो। पैरालंपिक्स में भारत ने जितने मेडल जीते उतने भारत ने अब तक के इतिहास में नहीं जीते थे। ओलंपिक में भी भारत का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा, क्योंकि युवाओं में जीत का विश्वास पैदा हुआ। केंद्र सरकार के टॉप्स कार्यक्रम के माध्यम से खिलाड़ियों को सहयोग और हर तरह के खेलों को प्रोत्साहन मिल रहा है। अब राष्ट्रीय खेल नीति- 2025 भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बन गई है।

> आज देश का लक्ष्य है- विकसित भारत, सशक्त भारत! हमें विकसित भारत के सपने को पूरा किए बिना नहीं रुकना है। मुझे विश्वास है, हर युवा इस सपने को अपना सपना बनाएगा, अपने कंधों पर देश की ये जिम्मेदारी लेगा।
>
> **- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

स्टार्टअप से यूनिकॉर्न की यात्रा

बीते 12 वर्षों में नौकरियों की प्रकृति में भी बहुत तेजी से बदलाव आया है। बदलती हुई परिस्थितियों में युवाओं के लिए नए सेक्टर उभर कर आए हैं। केंद्र सरकार इन नए सेक्टर को भी निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। इन 12 वर्षों में देश ने स्टार्टअप संस्कृति की नई क्रांति देखी है। 2014 में देश में जहां स्टार्टअप की संख्या सैकड़ों में थे, वहीं इनकी संख्या आज 2 लाख से ऊपर पहुंच गई है। अनुमान यह है कि इन स्टार्टअप ने कम से कम 21 लाख युवाओं को रोजगार दिए हैं। इन 12 वर्षों में ड्रोन सेक्टर में नया उछाल आया है। फर्टिलाइजर के छिड़काव से लेकर दवाइयों की सप्लाई तक में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। बीते 12 वर्षों में भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 57 करोड़ से अधिक लोन के आवेदन मंजूर किए हैं। करीब-करीब 12 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं, जिन्होंने मुद्रा योजना की मदद से पहली बार अपना स्वतंत्र काम शुरू किया है। पीएलआई योजना के तहत केंद्र सरकार मैन्यूफैक्चरिंग के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दे रही है। यह राशि भारत को दुनिया का मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार में भी सहायता करेगी।

युवा जोश को मिल रहे नए अवसर

जिस देश के युवा उत्साह और जोश से भरे हुए हों, उस देश की प्राथमिकता सदैव युवा ही होंगे। आज का भारत भी अपने सभी युवा साथियों के लिए वो प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहा है, जो राष्ट्र के सपनों को पूरा करने में मदद कर सके। भारत की डिजिटल क्रांति हो, भारत की स्टार्टअप क्रांति हो, इनोवेशन क्रांति हो, इन सबका सबसे बड़ा लाभ युवाओं को हो रहा है। आज भारत जिस तरह अपने रक्षा क्षेत्र में लगातार सुधार कर रहा है, उसका लाभ भी देश के युवाओं को हो रहा है। एक समय था, जब असॉल्ट राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट तक विदेशों से मंगवाया जाता था लेकिन आज सेना की जरूरत के सैकड़ों ऐसे सामान हैं, जो भारत में बन रहे हैं। यह सारे अभियान, भारत के युवाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर के आए हैं। हाल ही में देश ने स्पेस सेक्टर के द्वार युवा टैलेंट के लिए खोल दिए। परिणाम हुआ कि देखते ही देखते पहला प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इसी प्रकार एनीमेशन और गेमिंग सेक्टर, प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार लेकर आया है। एंटरटेनमेंट हो, लॉजिस्टिक हो, खेती-बाड़ी हो, हर जगह ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है।

बीते 12 वर्षों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में बेटियों की संख्या

में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। सेना के तीनों अंगों में अग्रिम मोर्चों पर महिलाओं की तैनाती का रास्ता खुल चुका है। आज महिलाएं भारतीय नौसेना में पहली बार अग्निवीर के रूप में, नाविक के रूप में शामिल हुई हैं। महिलाओं ने सशस्त्र बलों में लड़ाकू भूमिकाओं में भी प्रवेश करना शुरू किया है। केंद्र सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन की अनुमति भी दी गई है। इसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रशिक्षित 17 महिला कैडेटों का पहला बैच 28 मई से 13 जून के बीच रक्षा बलों में अधिकारियों के रूप में कमीशन हो गया है। अगस्त 2022 में यह कैडिट एनडीए में शामिल हुईं थीं। यह उपलब्धि देश भर की युवा महिलाओं की आने वाली पीढ़ियों को वर्दी में करियर बनाने तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।

आज युवाओं के लिए स्व-प्रमाणन की सुविधा है, जबकि पूर्व में प्रमाण पत्र को किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराना पड़ता था। ग्रुप-सी, डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिए गए हैं। तकनीक के इस युग में युवा गांव-गांव में नए डिजिटल उद्यमी बन रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं से देश में रोजगार और स्वरोजगार के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने युवाओं को 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन शुरू किया, लेकिन परिणाम देखिए कि अभी तक 12 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र इन मेलों के माध्यम से सौंपे जा चुके हैं। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना जैसी पहल आज आधार बन गई हैं। इतनी बड़ी युवा शक्ति जब राष्ट्र निर्माण में जुटेगी, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाएगा। हाल ही में प्रस्तावित राष्ट्रीय युवा नीति 2025 का ढांचा भविष्य के लिए जरूरी कौशल, उद्यमिता, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी, डिजिटल भागीदारी और टिकाऊ विकास जैसी उभरती प्राथमिकताओं पर और जोर देता है।

दरअसल, किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए जो ऊर्जा सबसे अहम होती है, वो ऊर्जा है युवा। उम्र के इस पड़ाव पर एक जोश और जुनून होता है। बहुत सारे सपने होते हैं और जब सपने संकल्प बन जाएं

युवा को कौशल प्रशिक्षण के अवसर

स्किल इंडिया मिशन 2015 में शुरू किया गया। कौशल विकास के बड़े नेटवर्क के जरिए कौशल, पुनः कौशल और अप स्किल प्रशिक्षण दिया जाता है। इस मिशन में कई स्तर पर व्यवस्था की गई...

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।
- जन शिक्षण संस्थान।
- नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम।

2.31 लाख नामांकन एआई की तैयारी के लिए कौशल विकास (SOAR) में कराए गए, यह 6 से 12वीं कक्षा के स्कूली छात्रों में एआई की बुनियादी कौशल का कोर्स है।

63 हजार से अधिक इंटर्नशिप के अवसर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में उपलब्ध है। इसकी शुरुआत अक्टूबर, 2024 में युवाओं को व्यवस्थित और पेड इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए हुई।

3.45 करोड़ से ज्यादा 18-28 साल के युवा औपचारिक कार्यबल में शामिल हुए, ईपीएफओ के आंकड़े।

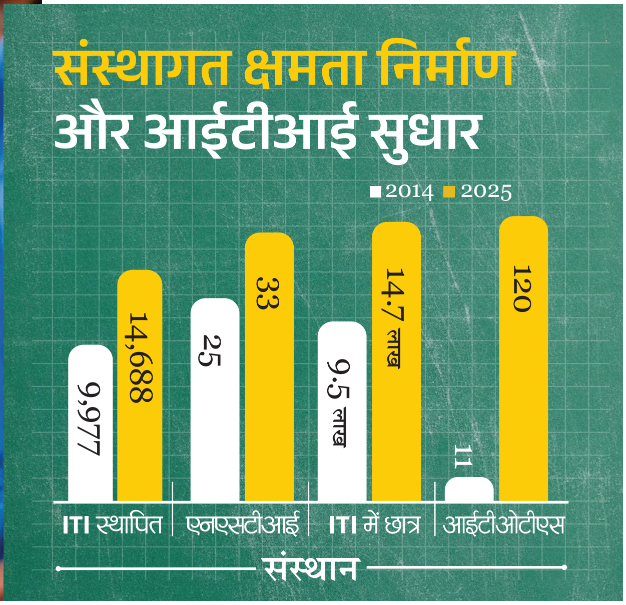

राष्ट्रीय युवा नीति...

राष्ट्रीय युवा नीति (एनवाईपी) 2014 ने देश में युवाओं के विकास के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया। नीति में 15-29 साल वालों को युवा माना गया। शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य, खेल, सामाजिक भागीदारी और सशक्तीकरण के क्षेत्र में समावेश और संस्थागत मजबूती पर ध्यान दिया गया।

> “आज पूरी दुनिया भारत के युवाओं को बहुत बड़े भरोसे के साथ देख रही है। उस भरोसे का कारण भारत के युवाओं के 'कौशल और संस्कार' हैं।"
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

और संकल्प के लिए जीवन जुट जाए तो जिंदगी भी सफल हो जाती है। भारत के युवाओं के लिए यह समय नए अवसरों का समय है। हर तरफ एक ही चर्चा है कि भारत का समय आ गया है, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, भारत का युवा। सही अर्थों में युवा शक्ति भारत की विकास यात्रा की प्रेरक शक्ति है। ऐसे में एक राष्ट्र जो समावेशी प्रगति का लक्ष्य रखता है, अपनी युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास में निवेश न करने का जोखिम नहीं उठा सकता है।

भारत विश्व की सर्वाधिक युवा शक्ति वाला राष्ट्र है। इतनी बड़ी युवा शक्ति वाला राष्ट्र छोटे सपने नहीं देख सकता। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप युवाओं को बड़ा सोचने का अवसर मिल रहा है, ताकि वे बड़े सपने देख सकें और उनकी पूर्ति कर सकें। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपनी युवा कल्याण नीतियों और दूरदर्शिता के जरिए उनकी क्षमता को पहचान रही है और उनके सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें अवसर मुहैया करा रही है।

चाहे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या कौशल विकास मिशन, स्टार्टअप क्रांति हो या युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाली नीतियां-आज केंद्र सरकार की सही नीयत और नए अवसरों के दम पर युवा देश की प्रगति के सारथी बन रहे हैं। उनका यही संकल्प, विकसित और सशक्त भारत के सपने को सच करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय

दिल्ली को 6 लेन सुरंग यूपी को नया हाईवे

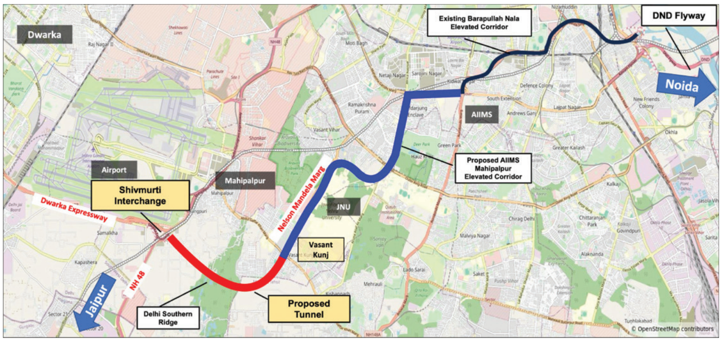

प्रतीकात्मक फोटो

मजबूत कनेक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से न सिर्फ यात्रा आसान होती है बल्कि व्यापार भी बढ़ता है। समय की बचत होती है, कम ईंधन खपत से प्रदूषण भी कम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि यह सिर्फ सड़क नहीं होती, समस्त क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, भंडारण और लॉजिस्टिक्स के नए रास्ते खोलती है। इसी कड़ी में 1 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस निर्णय से दिल्ली को छह लेन वाली सुरंग मिलेगी तो यूपी में बनेगा चार लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड नया हाइवे...

निर्णय : एनएच (ओ) योजना के अंतर्गत हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएम) पर द्वारका एक्सप्रेसवे (एनएच 248 बीबी) को नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, दिल्ली से जोड़ने वाले एनएच-148एई के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को स्वीकृति।

प्रभाव : यह परियोजना 8.1 किमी लंबी होगी, जिसकी कुल लागत 6,969.67 करोड़ रुपये है।

- इससे द्वारका एक्सप्रेसवे के शिवमूर्ति इंटरचेंज से नेल्सन मंडेला मार्ग और वसंत कुंज जुड़ जाएंगे।
- पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के बीच तेज कनेक्टिविटी स्थापित होगी।
- धौला कुआं-आईजीआई एयरपोर्ट, छतरपुर-महिपालपुर/आईजीआई एयरपोर्ट और रंगपुरी का ट्रैफिक जाम कम होगा।
- इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम, द्वारका, आईजीआई हवाई अड्डे और पश्चिम दिल्ली से दक्षिण दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को भी लाभ मिलेगा।
- भूमिगत दोहरी सुरंग से यातायात व्यवधान कम से कम होगा।
- दक्षिणी रिज वन (सुरंग का 1.98 किमी भाग रिज के नीचे से गुजरता है) संरक्षित रहेगा।
- परियोजना से प्रतिदिन लगभग 37,000 पैसेंजर कार यूनिट (**PCU**) के बराबर ट्रैफिक को राहत मिलेगी।
- परियोजना पीएम गति शक्ति के 6 आर्थिक केंद्रों और 4 लॉजिस्टिक्स केंद्रों को आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान करेगी।
- अनुमान है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रत्येक लेन-किलोमीटर के विकास से औसतन 264 व्यक्ति-दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और औसतन 55 व्यक्ति-दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा।

प्रतीकात्मक फोटो

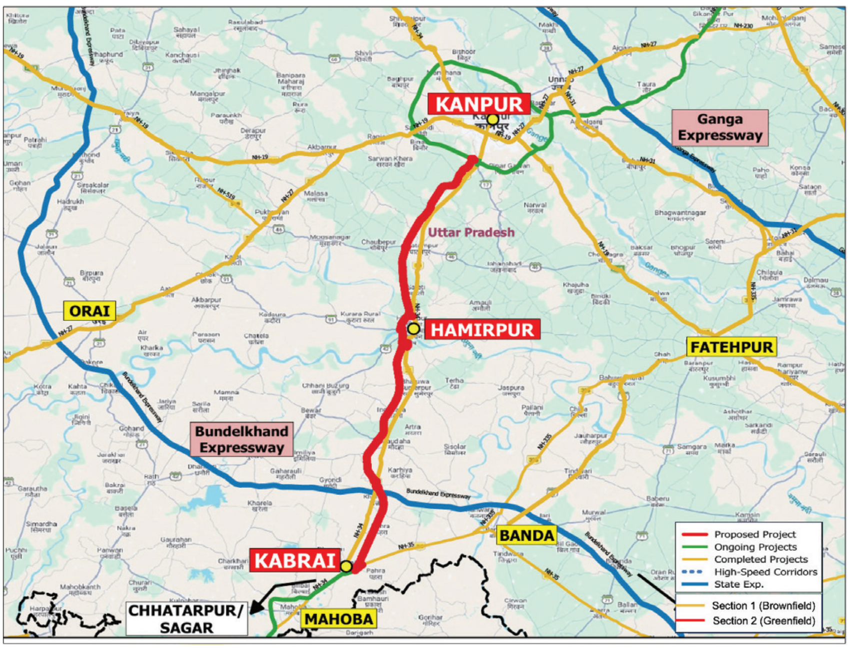

निर्णय : उत्तर प्रदेश में एनएच-34 के कानपुर-कबराई खंड के 4/6 लेन वाले एक्सेस-कंट्रोल्ड खंड के निर्माण को बीओटी (टोल) मोड पर 7145.14 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत से मंजूरी।

प्रभाव : यह चार लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड गलियारा है जिसमें भविष्य में छह लेन तक विस्तारित करने की व्यवस्था भी है। यह भोपाल-कानपुर आर्थिक गलियारे का हिस्सा है।

- यह परियोजना कानपुर और कबराई के बीच निर्बाध, उच्च गति की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
- साथ ही सागर, भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों तक आगे की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी, जिससे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों को मध्य प्रदेश के खनिज-समृद्ध, विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों से जोड़ने वाला एक आधुनिक पहुंच नियंत्रित आर्थिक गलियारा बनेगा।
- यह परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर, हमीरपुर और मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले महोबा को कवर करेगी।
- 80-100 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के लिए डिजाइन किया गया यह कॉरिडोर कानपुर और कबराई के बीच यात्रा समय को 3.5 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे (58 प्रतिशत) कर देगा।

एनडीए 3.0 में कुल 26 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है।

- साथ ही सड़क सुरक्षा में सुधार करेगा, वाहन परिचालन लागत को कम करेगा और यात्री एवं माल यातायात की कुशल आवाजाही को सुगम बनाएगा।
- परियोजना पीएम गति शक्ति के 4 आर्थिक केंद्रों और 10 लॉजिस्टिक्स केंद्रों को आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान करेगी।
- इस परियोजना से निर्माण के दौरान प्रति लेन प्रति किलोमीटर लगभग 11,188 प्रत्यक्ष और 13,985 अप्रत्यक्ष मानव-दिवस रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्वकर्ता बनेगा भारत

विकसित भारत का रास्ता युवाओं के कौशल और उनके सामर्थ्य पर ही टिका है। यही वजह है कि युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए केंद्र सरकार लगातार नए मौके दे रही है। इसी कड़ी में, पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को आगे बढ़ाने और उद्योगों के साथ उनका तालमेल बिठाने के लिए 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि 21वीं सदी में तरक्की वही देश करेंगे, जिनके पास कौशल, नए विचार और गुणवत्ता होगी। इसलिए केंद्र सरकार युवाओं को इन खूबियों से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। चाहे युवाओं का कौशल विकास करना हो, उनके नए विचारों को दुनिया भर में पहचान दिलानी हो या पहली बार नौकरी देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देना हो, सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके अच्छे नतीजे अब देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में दिख रहे हैं। दुनिया भर में भारत के युवाओं की मांग बढ़ी है। ये युवा अपनी योग्यता से न सिर्फ देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि विदेशों में रहकर भारत के साथ उनके रिश्तों को और मजबूत बना रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (वीबीआरवाई) से जुड़े लाभार्थियों, उद्योग प्रतिनिधियों और हितधारकों से कहा कि यह योजना भारत सरकार की रोजगार से जुड़ी प्रमुख प्रोत्साहन योजना है। दुनिया भारतीय युवाओं की क्षमताओं को पहचान रही है। सरकार भी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर युवा को अपनी क्षमता को सफलता में बदलने का अवसर मिले। वीबीआरवाई एक रोजगार योजना से कहीं अधिक है। यह पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवाओं की आकांक्षाओं को मजबूत करने और उद्योग तथा कार्यबल के बीच एक मजबूत सेतु बनाने के लिए तैयार की गई पहल है। जहां कई योजनाएं आमतौर पर कर्मचारियों या नियोक्ताओं पर केंद्रित होती हैं, वहीं यह कार्यक्रम एक साथ दोनों को

"प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना...यह रोजगार से कहीं बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

भारत के नवाचार इकोसिस्टम में वैश्विक रुचि

बीते 10 वर्षों में भारत में स्टार्टअप की संख्या करीब 500 से बढ़कर दो लाख से ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि फ्रांस में हुए 'इंडिया इनोवेट्स' कार्यक्रम ने भारतीय स्टार्टअप और दुनिया भर के निवेशकों को एक साथ आने का मौका दिया है। यहां एआई, स्पेस टेक, ग्रीन एनर्जी और बायोटेक जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर चर्चा हुई। ऐसे आयोजनों से साफ पता चलता है कि दुनिया का भरोसा भारत के नए इनोवेशन पर बढ़ रहा है। भविष्य की तकनीक बनाने में भारत की भूमिका अहम होती जा रही है, इसे विश्व स्वीकार भी करता है।

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

भारत की तरक्की और समाज को आगे बढ़ाने में महिलाओं का योगदान तेजी से बढ़ा है। उनकी सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए अब नाइट शिफ्ट से जुड़े नियमों में सुधार किए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम के मौके बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही दफ्तरों में सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत किए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं बिना किसी डर के नौकरी कर सकें।

खुल रहे नए बाजार

भारतीय उद्योगों के लिए नए बाजार खुले रहे हैं। यहां के पेशेवरों के लिए नये अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जब पूरी दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था की तैयारी कर रही है तब, भारत इसका नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। सरकार का ध्यान हमेशा रोजगार को सुरक्षा, गरिमा और सामाजिक संरक्षण से जोड़ने पर रहा है।

सहयोग करता है। सरकार उन युवाओं के साथ खड़ी है, जो पेशेवर सफर की शुरुआत कर रहे हैं। उन संस्थाओं को प्रोत्साहित करती है, जो नए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं।

योजना की उपलब्धियों को साझा करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि अब तक लगभग 70 लाख नई नौकरियां सृजित की गई हैं। इतनी ही संख्या में पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। लगभग 20 लाख युवा पहली नौकरी में छह महीने पूरे कर चुके हैं, जबकि इस उपलब्धि को पूरा करने पर लगभग 10 लाख लाभार्थियों को योजना के तहत पहले ही प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, "जब सरकार, उद्योग और युवा मिलकर काम करते हैं तो रोजगार सृजन में तेजी आती है। यह पहल एक नए भारत की झलक है जहां युवाओं को अवसर मिलते हैं, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है और रोजगार सृजन एक राष्ट्रीय मिशन बन जाता है।" ■

बंगाल रचेगा इतिहास... भारत की बढ़ेगी गति

भारत साल 2047 तक एक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के इस सपने को पूरा करने का सबसे बड़ा जरिया है-पूर्वी भारत का विकास! इसके लिए सरकार 'मिशन पूर्वोदय' पर काम कर रही है, जिसमें बंगाल की भूमिका बहुत अहम है। इसी कड़ी में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होने हुगली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-किसान की 23वीं किस्त जारी की। साथ ही, रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, मछली पालन और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन...

आजादी के बाद पश्चिम बंगाल के उज्ज्वल भविष्य के लिए जो सपना बंगाल की महान आत्माओं ने देखा था, आज एक तरह से पहली बार देश की जनता पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रही है। तारकेश्वर में समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग हैं - ईमानदार और पारदर्शी

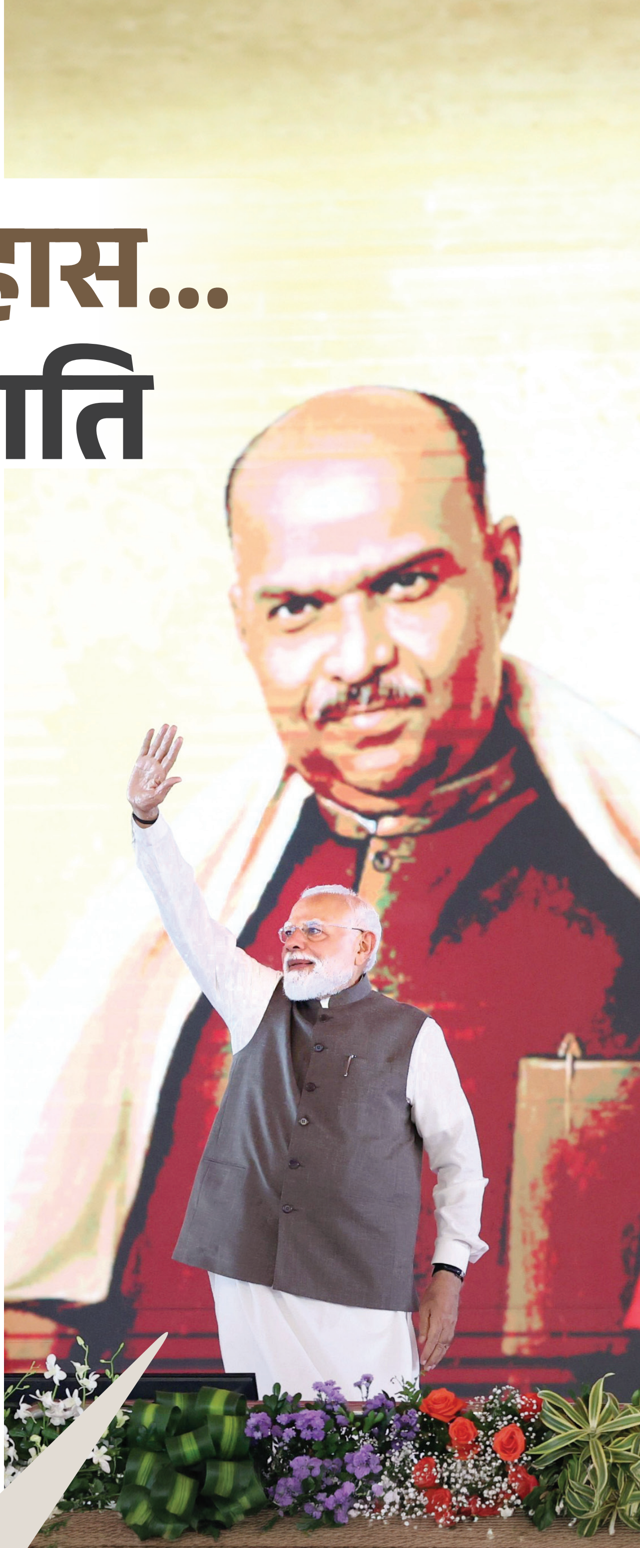

> *भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के इस संकल्प का सबसे बड़ा आधार है-पूर्वी भारत का विकास! इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी।*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

'पश्चिम बंगाल : विरासत, सद्भाव और विकास' रहा थीम

पश्चिम बंग दिवस समारोह का राज्य स्तरीय समारोह हुगली के तारकेश्वर में आयोजित किया गया जो डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ा एक ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। इस वर्ष के पश्चिम बंग दिवस का विषय : 'पश्चिम बंगालः विरासत, सद्भाव और विकास', राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

केंद्र सरकार की योजनाएं अब पश्चिम बंगाल को मिलनी शुरू

पीएम फसल बीमा योजना का शुभारंभ

- पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का शुभारंभ किया गया। इससे अब विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा।
- 2026-27 के दौरान, पीएमएफबीवाई पहल का लक्ष्य पश्चिम बंगाल में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है।

लगभग **28,140** करोड़ रुपये के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी।

किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जा सकेगी।

पश्चिम बंगाल में एग्रीस्टैक का शुभारंभ

- डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल में एग्रीस्टैक का शुभारंभ।
- इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा।
- यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी। किसान-केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी।

राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन का शुभारंभ

- पश्चिम बंगाल में स्थायी, रसायन-मुक्त कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन का शुभारंभ।
- वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत, राज्य 17,300 हेक्टेयर में फैले 346 प्राकृतिक कृषि क्लस्टर स्थापित करेगा।
- जैव-इनपुट संसाधन केंद्र बनाएगा। पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखियों को सक्रिय करेगा।
- एकीकृत कृषि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) का कार्यान्वयन भी शुरू।

राज्य को विकास परियोजनाओं की सौगात

- दक्षिण 24 परगना के फ्रेजरगंज में आधुनिक और क्षमता-विस्तारित मत्स्य बंदरगाह और बीरभूम के सैंथिया में नवनिर्मित आधुनिक मछली बाजार का उद्घाटन।
- नादिया जिले के हरिंगहाटा में बकरियों के लिए स्थापित क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला और वीर्य बैंक का भी उद्घाटन।
- लगभग 590 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया।
- हावड़ा में संकराइल-संतरागाछी लिंक लाइन प्रोजक्ट राष्ट्र को समर्पित।
- हावड़ा में 300 बिस्तर वाले संभागीय रेलवे अस्पताल की आधारशिला।
- पूर्वी मेदिनीपुर जिले में हौर और राधामोहनपुर के बीच बनने वाले ओवरब्रिज की आधारशिला भी रखी।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) के अंतर्गत विकसित 49 सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी

पश्चिम बंग दिवस समारोह के दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इस किस्त के अंतर्गत, देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रु. से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रु. से अधिक की राशि जमा की गई, जिससे राज्य में इस योजना के अंतर्गत कुल वितरण राशि 15,000 करोड़ रु. से अधिक हो गई। 2019 में योजना की शुरुआत के बाद से कुल वितरित राशि 4.46 लाख करोड़ रु. से अधिक हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा और उनके जीवन में खुशहाली बढ़ेगी।

शासन! और दूसरा- कानून का राज! पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया-लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जनकल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है।

पूर्वी भारत में विकास और समृद्धि प्रवेश-द्वार के रूप में उभर रहा 'ओडिशा'

'भारत के विकास के लिए पूर्वी भारत का विकास' सरकार की यह नीति पूर्वी राज्यों की विशाल संभावनाओं को सामने ला रही है। सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, राजमार्ग, आर्थिक कॉरिडोर, पत्तन, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा से लेकर आधुनिक उद्योगों में रिकॉर्ड निवेश कर रही है। इसी क्रम में 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान ओडिशा सरकार के दो साल पूरे होने पर मयूरभंज जिले में आयोजित कार्यक्रम में 47,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास...

ओडिशा सरकार के दो साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश, रोजगार और जन-कल्याणकारी योजनाओं से राज्य का तेजी से विकास हो रहा है और लोगों का जीवन बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 47 हजार करोड़ की जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया , उससे लोगों के लिए परिवहन संपर्क, सार्वजनिक सेवाओं, आर्थिक अवसरों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने कहा कि पहाड़पुर गांव को सौर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा और हर घर में सौर ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहाड़पुर एक मॉडल सौर ऊर्जा

> “
> *आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हम आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ाई की बेहतर सुविधा मिले... इसके लिए देश में करीब 500 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए हैं।*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला

- 600 मेगावाट की अपर इंद्रावती पंप स्टोरेज परियोजना।
- आईबी थर्मल पावर स्टेशन की चरण-II विस्तार परियोजना, जिसमें 660 मेगावाट की दो इकाइयां।
- झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड परियोजना।
- नुआपड़ा से घाटीपाड़ा तक एनएच-353 के एक खंड का चार लेन का निर्माण।
- कुसुमदिही मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना।
- इग्नू क्षेत्रीय केंद्र और रायरांगपुर में इंडोर बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन

- बौध में 300 बिस्तरों वाले जिला मुख्यालय अस्पताल भवन।
- ओडिशा के विभिन्न जिलों में 24 अटल बस स्टैंड और नौ स्वचालित परीक्षण केंद्र।
- एनएच-57 पर नयागढ़ टाउन बाईपास, कुसुमी स्मार्ट सिंचाई परियोजना।
- रायरांगपुर में खेल परिसर और जनजातीय अनुसंधान केंद्र।

जनजातीय समुदाय का इन योजनाओं से हो रहा विकास...

- एनीमिया बीमारी के खिलाफ देशव्यापी अभियान।
- जल जीवन मिशन से सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था।

500 के करीब एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित किए गए।

750 एकलव्य स्कूलों को दी गई है मंजूरी।

1.5 करोड़ से ज्यादा जनजातीय छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का दौरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा किया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पवित्र स्थलों 'संथाली जाहेरा' और 'हो जाहेरा' में पूजा-अर्चना की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओडिशा सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की थीम 'विकास रा धारा, ओडिशा सारा' रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए, पीएम मोदी ने उनके मयूरभंज की मिट्टी से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक के सफर को ओडिशा और देश के लिए गर्व का विषय बताया।

संचालित गांव के रूप में उभरेगा। ओडिशा के संसाधनों को सरकार विकास और समृद्धि के अवसर में बदल रही है। उन्होंने 'उत्कर्ष ओडिशा' जैसी पहल का जिक्र किया। साथ ही, कहा कि इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना है, ताकि पूरे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस पहल के तहत, ओडिशा ने पहले ही लगभग 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर लिए हैं। साथ ही कई बड़ी परियोजनाएं, जिनकी लागत 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, वर्तमान में इन पर कार्य चल रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। ■

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का अयोजन

सबको जोड़ता, सबको साथ लाता योग

प्रधानमंत्री का योग दिवस पर पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला व अन्य 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग करते हुए।

भारत की हजारों वर्ष पुरानी योग परंपरा आज पूरी दुनिया के लिए नई उम्मीद बन चुकी है। यह मानवता को स्वस्थ, संतुलित और शांत जीवन का मार्ग दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से शुरू हुआ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अब वैश्विक जनआंदोलन का रूप ले चुका है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित रेड रोड से 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व पीएम मोदी ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि योग सबको जोड़ता है और लाता है साथ...

गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है- युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त स्वप्न अव-बोधस्य, योगो भवति दुःखहा॥ अर्थात्, संतुलित आहार-विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से संतुलित नींद और जागने से, योग दुःखों का नाश करने वाला हो जाता है। यह संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का भी आधार है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं, बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको, योग हमें जीवन को संतुलित तरीके में जीने की कला सिखाता है।

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का पीएम मोदी ने किया नेतृत्व

- कोलकाता के रेड रोड पर 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय आयोजन।
- योग अभ्यासकर्ताओं के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में पीएम मोदी ने भाग लिया।
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 का विषय, 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग'।
- यह विषय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और स्वस्थ, सक्रिय और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था पर है।
- वर्ष 2015 में इसकी स्थापना के बाद से, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को अपनाया।

योग दिवस समारोह विश्व भर में लगभग **2,500** स्थानों पर आयोजित किया गया जिसमें 210 से अधिक दूतावासों की रही भागीदारी।

- नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मैसूर, न्यूयॉर्क (संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय), श्रीनगर और विशाखापत्तनम सहित विभिन्न स्थानों पर मुख्य समारोह का हुआ आयोजन।

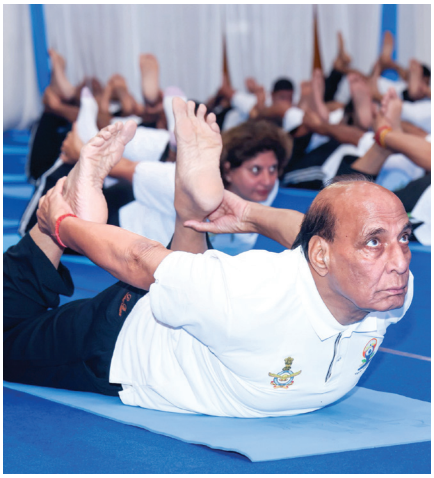

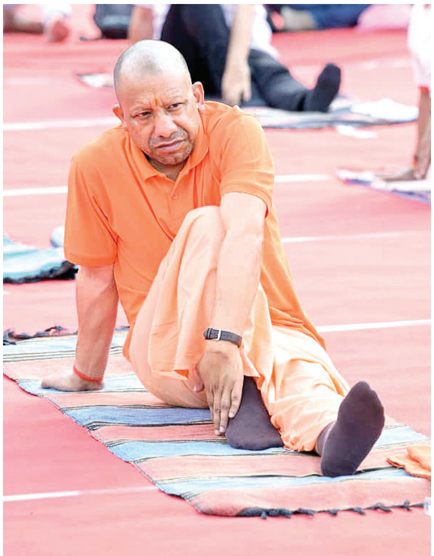

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया योग।

उत्तराखंड के ऋषिकेश में पवित्र परमार्थ घाट पर योग करते लोग।

योग, क्या करें और क्या न करें, सिखाता है और जब हम शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तब हम स्वस्थ रहते हैं।

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसीलिए, योग के विषय में "युक्त चेष्टस्य कर्मसु" कहा गया है। यानी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध! ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते

> *जब समाज स्वस्थ होगा, तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं आप सबके लिए कामना करता हूं, "सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।" इसी के साथ आप सभी को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

नई दिल्ली स्थित हुमायूं मकबरा परिसर में योग करते लोग।

भारतीय नौसेना के शिप 'सुदर्शनी' ने अमेरिका के वर्जीनिया राज्य के नॉरफॉक में 'टॉल शिप' पर एक योग सत्र आयोजित किया।

भारतीय नौसेना ने अनोखे तरीके से पानी के नीचे किया योग।

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन लेह में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हुए शामिल।

हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज का यह दिन अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए, संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे। अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। ■

निष्ठा और समर्पण को नमन

बीते कुछ वर्षों में पद्म पुरस्कारों ने लुटियंस दिल्ली के गलियारों से निकलकर भारत के सुदूर गांव, जंगल तक का सफर तय किया है। आज का 'पद्म सम्मान' सही मायनों में 'पीपुल्स पद्म' बन चुका है, जहां पहचान का आधार कोई रसूख नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में लाया गया सकारात्मक बदलाव है। पद्म सम्मान पाने वाले इस बात के जीवंत प्रमाण हैं कि प्रतिभा और सेवा किसी खास परिवेश की अधीन नहीं होती। इस विशेष आलेख में देश के उन 'नायकों' की प्रेरक कहानियां बता रहे हैं जिन्होंने देश का मस्तक किया है ऊंचा...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 23 जून को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह-II में वर्ष 2026 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। दूसरे चरण के इस अलंकरण समारोह में दो पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 57 को पद्म श्री सम्मान दिए गए। केंद्र सरकार ने इसी साल 25 जनवरी को एक संयुक्त सहित 131 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की थी, पहले चरण का अलंकरण समारोह 25 मई, 2026 को हुआ था।

सम्मान समारोह का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

पद्म विभूषण

पी नारायणन

नारायणजी के नाम से लोकप्रिय पी. नारायणन राष्ट्रवादी पत्रकारिता के दिग्गज और एक महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक संगठनकर्ता हैं। नारायणजी ने केरल में कभी हाशिए पर रहने वाली विचारधारा को व्यक्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 28 मई, 1936 को केरल के थोडुपुझा के मानकड़ में जन्मे नारायणन की शिक्षा महात्मा गांधी कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉलेज, तिरुवनंतपुरम में हुई। उनकी राजनीतिक यात्रा उनके छात्र दिनों में शुरू हुई जब वह आरएसएस में शामिल हो गए। उन्होंने मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य केरल में प्रचारक के रूप में सेवा करते हुए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पत्रकारिता से परे, नारायणन ने एक विद्वान लेखक और एक दक्ष अनुवादक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के. टी. थॉमस

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के. टी. थॉमस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। 30 जनवरी, 1937 को जन्मे थॉमस ने अपनी कॉलेज की शिक्षा सी.एम.एस. कॉलेज, कोट्टायम में प्राप्त की। उन्हें 1985 में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 1995 में केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) के रूप में नामित किया गया था। मार्च 1996 में, उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। वह वर्ष 2002 में उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए। थॉमस को आपराधिक कानून, पुलिस सुधार और निजी व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। थॉमस को वर्ष 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

पद्म भूषण

डॉ. विजय अमृतराज

डॉ. विजय अमृतराज भारत के महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। 14 दिसंबर, 1953 को चेन्नई में जन्मे, डॉ. विजय ने 14 साल की उम्र से जूनियर प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई यादगार जीत दर्ज की। वे भारतीय खेलों में एक प्रतिष्ठित हस्ती रहे हैं। डॉ. विजय को उनके कार्यों और योगदान के लिए वर्ष 1983 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें वर्ष 2022 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के सर्वोच्च सम्मान गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे आज भी विभिन्न मंचों पर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं और उन मूल्यों की वकालत करते हैं जो हमेशा उनके करीब रहे हैं, जैसे भारत की उत्कृष्टता, अखंडता और दृढ़ मान्यता।

डॉ. एसकेएम. मलियानन्दन

एसकेएम. कंपनी समूह के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. एसकेएम. मलियानन्दन एक प्रसिद्ध उद्यमी होने के साथ विभिन्न सामाजिक कल्याण ट्रस्टों के संस्थापक और एक उपभोक्ता कार्यकर्ता हैं। वह पूरे विश्व में योग और ध्यान के प्रसार के साथ निःस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाते हैं। 18 मई, 1945 को तमिलनाडु के इरोड जिले में जन्मे डॉ. मलियानन्दन ने स्कूली शिक्षा ही प्राप्त की है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित और अशिक्षित लोगों के स्वरोजगार का बीड़ा उठाया और पूरे वर्ष नौकरी के अवसर प्रदान किए। उन्होंने बाजार और मूल्य निर्धारण में किसानों की समस्याओं का अध्ययन, विश्लेषण और पोल्ट्री की उभरती बीमारियों को रोकने के लिए कई संगोष्ठियां तथा बैठकों का आयोजन किया। उन्हें 2013 में सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

पद्म भूषण

मंमूट्टी

मोहम्मद कुट्टी पन्नापराम्बिल इस्माइल उर्फ मंमूट्टी एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं। वह दक्षिण भारतीय भाषा सिनेमा में सक्रिय हैं, लेकिन मुख्य रूप से मलयालम फिल्म उद्योग में काम करते हैं। 7 सितंबर, 1951 को जन्मे मंमूट्टी के पिता एक कृषक थे, जिनकी जड़ें कृषि और ग्रामीण जीवन में रची-बसी थी। पांच दशक के करियर में मंमूट्टी ने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें मुख्य रूप से मलयालम के साथ-साथ कई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी फिल्में भी शामिल हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में से एक माना जाता है। सिनेमा में अपने योगदान के अलावा, उन्होंने मानवीय प्रयासों और सामुदायिक विकास में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। फिल्मों और कला में योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1998 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

वेल्लापल्ली नटेशन

वेल्लापल्ली नटेशन केरल के एक प्रमुख सामाजिक नेता और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वह श्री नारायण धर्म परिपालन (एसएनडीपी) योगम के महासचिव और श्री नारायण ट्रस्ट के सचिव भी हैं। 10 सितंबर, 1937 को केरल के अलप्पुझा जिले के कनिचिकुलंगरा में जन्मे नटेशन, पिछड़े वर्गों की सामाजिक और शैक्षिक उन्नति के लिए प्रतिबद्ध एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। नटेशन ने श्री नारायण गुरु द्वारा वर्ष 1903 में स्थापित एसएनडीपी योगम आंदोलन को नई ऊर्जा दी। उनके नेतृत्व में, वर्ष 1996 के बाद से संगठन का विस्तार व्यापक जमीनी स्तर पर पहुंचा और यह एक आधुनिक सामाजिक-आर्थिक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। उनके नेतृत्व में शाखाओं की संख्या 3,000 से बढ़कर 6,000 से अधिक हो गई। नटेशन ने शाखा स्तर पर परिवार इकाइयों की भी शुरुआत की और संगठन को प्रत्येक घर तक पहुंचाया।

पद्म भूषण

डॉ. दत्तात्रेयुडु नोरी

डॉ. दत्तात्रेयुडु नोरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रशंसित ऑन्कोलॉजिस्ट, अग्रणी चिकित्सक और एक महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। चार दशकों से अधिक के अपने करियर के दौरान, उन्होंने न्यूयॉर्क में विश्व प्रसिद्ध कॉर्नेल मेडिकल सेंटर में ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर और अध्यक्ष तथा कैंसर केंद्र के निदेशक के पद पर कार्य किया है। उन्हें कैंसर की कई उपचार तकनीकों का पता लगाने में अग्रणी भूमिका के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है। इससे इलाज की दरों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और वैश्विक स्तर पर मरीजों के जीवन को बचाने में मदद मिली। 18 अक्टूबर, 1947 को जन्मे डॉ. नोरी ने कैंसर केंद्रों की स्थापना के लिए विभिन्न सरकारों और निजी संगठनों के साथ मिलकर अपनी विशेषज्ञता साझा की। भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया था।

शिबू सोरेन, मरणोपरांत

श्रद्धापूर्वक "दिशोम गुरु" के नाम से पहचान रखने वाले शिबू सोरेन भारत के प्रमुख आदिवासी जननेता, सामाजिक सुधारक तथा झारखंड आंदोलन के मुख्य शिल्पकारों में से एक थे। वे आदिवासी समुदायों की गरिमा, पहचान, न्याय तथा स्वशासन से संबंधित दीर्घकालीन आकांक्षाओं के सुदृढ़ एवं नैतिक एवं राजनीतिक प्रवक्ता थे। उनका जीवन जल, जंगल एवं जमीन के नैतिक संरक्षण के सिद्धांत की स्थायी अभिव्यक्ति का द्योतक रहा है। 11 जनवरी, 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में जन्मे सोरेन एक साधारण संथाल आदिवासी परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री के रूप भी काम किया। लाखों लोगों के लिए सोरेन केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि स्मृति, प्रतिरोध और आशा के संरक्षक थे। उन्होंने आदिवासी अधिकारों, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदायों के अधिकारों की निरंतर वकालत की। शिबू सोरेन का 4 अगस्त 2025 को निधन हो गया।

अलका याग्निक

अलका याग्निक भारत की एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं। चार दशक से अधिक की गायन यात्रा में, उनका मधुर स्वर, कलात्मक उत्कृष्टता और निरंतर समर्पण ने भारतीय सिनेमा एवं सांस्कृतिक विरासत को अत्यधिक समृद्ध किया है। उन्होंने अपनी मां शुभा याग्निक के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 20 मार्च, 1960 को कोलकाता में जन्मी याग्निक ने एक ऐसी समृद्ध शास्त्रीय संगीत नींव के साथ अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिसने उनकी विशिष्ट कलात्मक संवेदनशीलता और मधुर पहचान को आकार दिया। याग्निक यूट्यूब पर अब तक की सबसे लोकप्रिय संगीत कलाकार हैं। याग्निक को भारतीय संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। दशकों से उनकी निरंतर कलात्मक उपलब्धियां और निरंतर लोकप्रियता उनकी असाधारण प्रतिभा और कला के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण रहा है।

भारत

ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की सशक्त आवाज

सरकार की नीतियों और दूरदर्शी नेतृत्व ने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया है। आज भारत सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील और गरीब देशों) की उम्मीदों और जरूरतों की बुलंद आवाज बन चुका है। दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और साख का ही प्रमाण है कि लगातार आठवीं बार जी-7 शिखर सम्मेलन में निमंत्रण मिला। इसी क्रम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रहे। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की और आपसी सहयोग के साथ-साथ दुनिया के अहम मुद्दों पर विस्तार से की चर्चा...

वैश्विक संबंधों को मजबूत करने और दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियों पर चर्चा के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहे। वहां उन्होंने जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया और कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विवाटेक सम्मेलन में भाग लिया जो यूरोप के प्रौद्योगिकी और नवाचार का सबसे बड़ा सम्मेलन था। इस सम्मेलन में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन बनाया गया था। इसके अलावा पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों 'भारत इनोवेट्स' में भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका

> *जी-7 की पूंजी, भारत की प्रतिभा और ग्लोबल साउथ के देशों के स्वामित्व को जोड़ते हुए हम 'इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड' यानी IMPACT, बनाने पर विचार कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे गलियारे बनाना होना चाहिए, जो व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अवसरों को आपस में जोड़ें।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया यात्रा

भारत और स्लोवाकिया ने 1993 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से पारंपरिक मैत्री और विश्वास, समानता तथा आपसी सम्मान के आधार पर बहुआयामी सहयोग विकसित किया है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए अधिक संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देने में 'भारत-स्लोवाकिया संयुक्त आर्थिक समिति' की भूमिका को और मजबूत करने पर सहमति बनी। पीएम मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने बैठक में बढ़ते आर्थिक, व्यापारिक और लोगों के बीच आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए सीधे हवाई संपर्क की संभावनाएं तलाशने को भी प्रोत्साहित किया। दोनों नेता, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में आपसी आदान-प्रदान को और गहरा करने के मकसद से, छात्रों, शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं की आवाजाही को बढ़ावा देने पर सहमत हुए।

'ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, फर्स्ट क्लास' सम्मान

स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, प्रथम श्रेणी' से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और वहां के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के 1.4 अरब लोगों तथा दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को समर्पित किया।

पीएम मोदी को अब तक कुल 34 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है।

विश्वास, सबका प्रयास' के सिद्धांतों पर आधारित भारत के समावेशी विकास का जिक्र किया। फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने 'सभी के लिए संतुलित, साझा और टिकाऊ आर्थिक विकास की ओर बढ़ने' पर आयोजित आउटरीच सत्र को संबोधित किया। साथ ही 'इंश्योरिंग ए सेफ, रैपिड एंड एफिशिएंट रोल आउट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' विषय पर आयोजित सत्र को भी संबोधित किया। जी-20 की अध्यक्षता में भारत के समावेशी विकास का मंत्र 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के आदर्श वाक्य के रूप में दिखा था। इसी प्रकार का दृष्टिकोण भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे की परिकल्पना का भी आधार रहा है। जिसका उद्देश्य

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्लोवाकिया की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बहादुर सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी।

आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाना, निवेश और रोजगार के अवसर सृजित करना तथा नवाचार को बढ़ावा देना है। संकटों और संघर्षों का वैश्विक दक्षिण के देशों पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन देशों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय एकजुटता और सहयोग का पीएम मोदी ने आह्वान किया। उन्होंने सुझाव दिया कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों

'भारत इनोवेट्स 2026' कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लिया भाग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में संयुक्त रूप से 'भारत इनोवेट्स 2026' का उद्घाटन किया। 'भारत इनोवेट्स' में भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप, इनोवेटर्स, रिसर्चर और इन्वेस्टर्स, वैश्विक इनोवेशन फंड्स एक मंच पर साथ आए। दुनिया भर के 350 से अधिक प्रमुख निवेशकों और वेंचर कैपिटलिस्ट ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि स्टार्टअप का आकलन केवल उनके बाजार मूल्यांकन से नहीं, बल्कि मानवता पर उनके प्रभाव से किया जाना चाहिए। उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य देखभाल, मेडटेक, उन्नत सामग्री, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में फैले स्टार्टअप और इनोवेटर्स के साथ भी बातचीत की।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने आपसी और वैश्विक मुद्दों पर खुलकर बात की। बैठक में पीएम मोदी ने होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार को बनाए रखने के साथ-साथ नाविकों की सुरक्षा को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को रोकने और वहां शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों की तारीफ भी की। इसके अलावा, दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 की अपनी वाशिंगटन बैठक के बाद से रक्षा, आधुनिक टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्रों में हुई तरक्की की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर हो रही बातचीत पर संतोष जताया। अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द संतुलित समझौता तैयार करें, जिससे दोनों देशों को फायदा हो।

को ऐसे सहायता तंत्र विकसित करने चाहिए, जो विकासशील देशों को आर्थिक लचीलापन प्रदान कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने "संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय लामबंदी साझेदारी" या इम्पैक्ट के गठन का सुझाव रखा जिसमें जी-7 की पूंजी, भारत की प्रतिभा और ग्लोबल साउथ के स्वामित्व को जोड़ा जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच सम्मेलन के दौरान हुई बैठक में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसके तहत अगले पांच सालों में आपसी व्यापार को दोगुना करने तथा छोटे उद्योगों, रेलवे और विमानन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया गया। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने और 'हॉराइजन 2047 रोडमैप' के जरिए तकनीक और इनोवेशन को मजबूत करने पर बात की। शिक्षा के क्षेत्र में कानपुर में एयरोनॉटिक्स के लिए एक 'उत्कृष्टता केंद्र' स्थापित किया जाएगा और फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा, लोथल के समुद्री विरासत परिसर सहित दोनों देशों के संग्रहालयों के बीच सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और यूक्रेन व पश्चिम एशिया जैसे वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। ■

भारत और सेशेल्स की दोस्ती के स्वर्णिम 50 वर्ष

हिंद महासागर में भारत के अहम समुद्री पड़ोसी और रणनीतिक सहयोगी देश सेशेल्स के साथ राजनयिक संबंधों के 50वें वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 से 29 जून तक वहां की यात्रा की। यात्रा के दौरान न केवल दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने। यही नहीं, सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होकर उन्होंने दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों को दी एक नई ऊंचाई...

सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अक्षय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर मजबूत सहमति बनी। हिंद महासागर क्षेत्र में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'गार्जियन ऑफ द ब्ल्यू हॉरिजन' से किया गया सम्मानित

सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के विशेष सम्मान 'गार्जियन ऑफ द ब्ल्यू हॉरिजन' से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री को यह सम्मान उनके हरित नेतृत्व, विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने के प्रयासों, नीली अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, समुद्री संसाधनों के प्रबंधन के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया है। यह सम्मान हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता विकास, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास की पहलों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को सेशेल्स द्वारा दिए जाने वाले महत्व को दर्शाता है।

सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ

सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में बतौर सम्मानित अतिथि पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी सेशेल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियां भी सेशेल्स की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में शामिल हुईं।

यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य...

- भारत और सेशेल्स के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर होगा काम, इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा।
- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभव को सेशेल्स के साथ किया जाएगा साझा।
- भारत सेशेल्स के सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग में देगा योगदान।
- जन औषधि पर एमओयू, इससे यहां के लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दर पर दवा उपलब्ध होगी।
- स्पेस के क्षेत्र में दोनों देशों ने मिलकर आगे बढ़ने का लिया है निर्णय।

सेशेल्स के नेशनल असेंबली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा, "हिंद महासागर क्षेत्र का यह पहला देश है जहां मैंने प्रधानमंत्री के रूप में 2015 में दौरा किया था। प्रधानमंत्री के रूप में अफ्रीकी देश की यह मेरी पहली यात्रा भी थी। मैं यहां इसलिए आया क्योंकि मेरा मानना था कि सेशेल्स हिंद महासागर के लिए भारत के दृष्टिकोण में एक विशेष स्थान रखता है। आज, जब मैं एक दशक बाद यहां फिर आया हूं, तो वह दृढ़ विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है।" पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमारी दोस्ती पचास साल पहले हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापना के साथ शुरू नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। अगस्त 1770 में, सेंट ऐनी द्वीप पर थेलेमाक जहाज पर सवार होने वालों में पांच भारतीय थे। उस यात्रा ने कई और लोगों को रास्ता दिखाया जो उसका अनुसरण कर रहे थे।

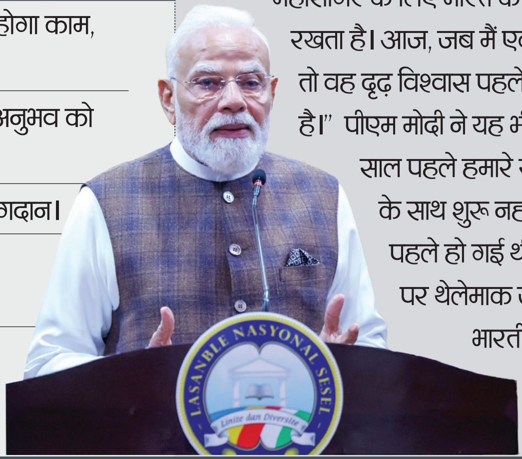

सेशेल्स को भारत का उपहार

- एक तेज गति वाला गश्ती पोत उपहार स्वरूप प्रदान किया गया
- सेशेल्स रक्षा बल को 10 उपयोगी वाहन और लेजर रेडियल श्रेणी की 5 नौकाएं
- **6** एम्बुलेंस
- **500** मीट्रिक टन चावल
- **8500** मीट्रिक टन सीमेंट

मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों सहित क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की विकास प्राथमिकताओं के समर्थन तथा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और स्थायी साझेदारी को गहरा करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक संयुक्त स्मारक लोगो भी जारी किया।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

महिला खेल जगत का स्वर्णिम युग

खेलो इंडिया से वैश्विक मंच तक

आज का भारत बदल रहा है। इस बदलाव की बुलंद तस्वीर एक बार फिर से खेल के मैदान से आई है। विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए महिला खिलाड़ियों ने न केवल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तिरंगा लहराया है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं को नए सपने देखने का हौसला भी दिया है। ओलंपिक के पोडियम से लेकर क्रिकेट की पिचों तक, इन बेटियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन यह साबित करता है कि जब बात देश का गौरव बढ़ाने की हो, तो नए भारत की नारी शक्ति किसी से पीछे नहीं है। इस कड़ी में महिला हॉकी खिलाड़ी और एथलिटों ने वैश्विक स्तर पर बढ़ाया है देश का मान...

बुनियादी ढांचे में सुधार, सही प्रोत्साहन और 'खेलो इंडिया' जैसी दूरदर्शी सरकारी नीतियों का असर आज देश के खेल परिदृश्य में साफ नजर आ रहा है। देश के छोटे-छोटे गांवों और कस्बों से निकलकर महिला खिलाड़ी आज वैश्विक प्रतियोगिताओं में इतिहास रच रही हैं। सरकार द्वारा खेल-खिलाड़ियों को दिए जा रहे निरंतर समर्थन और आधुनिक सुविधाओं ने उनकी प्रतिभा को तराशने का काम किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एफआईएच हॉकी महिला नेशंस कप 2026 जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हरा कर भारत ने दूसरी बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है।

वहीं दूसरी ओर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला खिलाड़ियों की 4x100 मीटर रिले टीम ने गोल्ड जीतकर तिरंगे का शान बढ़ाया। ओलंपियन श्रावणी नंदा, स्नेहा शानुवल्ली, सुदेशना शिवंकर और तमन्ना ने महिलाओं की 4x100 मीटर रिले फाइनल में 43.85 सेकेंड का सीजन का सर्वश्रेष्ठ समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। इस ऐतिहासिक सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यदि अवसर और संसाधन मिले तो भारत की बेटियां किसी भी क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सकती हैं।

प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी गौरव और खुशी लेकर आए हैं। एफआईएच हॉकी विमेंस नेशंस कप जीतने पर महिला टीम को बधाई। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण प्रदर्शन किया। टीम को शुभकामनाएं। आशा है कि यह जीत कई अन्य खिलाड़ियों को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करेगी।

Narendra Modi
@narendramodi

2014 के बाद से हमने नीतियों के स्तर पर बड़े रिफॉर्म किए हैं। इससे रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ने के साथ ही हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी अभूतपूर्व गति से बढ़ा है।

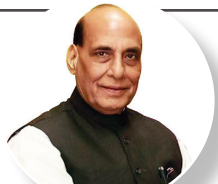

Rajnath Singh
@rajnathsingh

भारतीय सशस्त्र बल हमेशा से राष्ट्रीय एकता की प्रतीक रही हैं। यहाँ भाषा, क्षेत्र, जाति या प्रांत नहीं, बल्कि केवल राष्ट्र सर्वोपरि होता है। हमारी सेनाएँ उस अखंड भारतीय भावना का जीवंत स्वरूप हैं, जहाँ विविधता ही सबसे बड़ी शक्ति है।

Amit Shah
@AmitShah

मोदी जी के नेतृत्व में आज टेक्नोलॉजी आधारित सुशासन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ रहा है। आज गांधीनगर से 'PM फैमिली केयर ट्रैकर' (FCT) के पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। यह डैशबोर्ड विभिन्न प्रकार के डेटा को जोड़कर केंद्र व राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद परिवारों के दरवाजे तक पहुंचाएगा। साथ ही PM ई-बस सेवा को हरी झंडी दिखाई।

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

सशक्त किसान, समृद्ध राष्ट्र की दिशा में एक और कदम!

🇮🇳 देश के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 23वीं किस्त आज प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने जारी की।

हुगली, पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान देश के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹18,880 करोड़ से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की गई।

Jyotiraditya M. Scindia
@JM_Scindia

Sanchar Saathi doing what it does best. Reuniting citizens with their lost/stolen handsets.

Your phone's true saathi.

#SancharSaathi

Ram Mohan Naidu Kin...
@RamMNK

The Made in India C-295 reflects a stronger aerospace ecosystem, greater opportunities for MSMEs and skilled talent, and a stronger resolve towards an Aatmanirbhar Bharat.

भारत की लीडरशिप पर 4 फीसदी लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा

अमेरिका और चीन पर घटा ऑस्ट्रेलियाई लोगों का विश्वास

ऑस्ट्रेलियाई सर्वे में लोगों को भारत पर सबसे ज्यादा भरोसा

विश्वसनीयता में चीन, अमेरिका को पीछे छोड़ कई गुना आगे निकल गया भारत

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की दुनियाभर में छवि लगातार मजबूत हो रही है। तेजी से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे भारत पर इंटरनेशनल लेवल पर विश्वास भी बढ़ रहा है। इसका उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित थिंक-टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट के सर्वे में भी दिखाई देता है, जिसमें भारत को अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों से भी ज्यादा भरोसेमंद बताया गया है। बीते 23 जून को रिलीज हुए लॉवी इंस्टीट्यूट के सर्वे के मुताबिक, 50 फीसदी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भारत पर भरोसा करते हैं। इसके मुकाबले महज 31 प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई अमेरिका पर विश्वास जताते हैं। वहीं, चीन पर भरोसा करने वालों की संख्या 28 प्रतिशत और रूस पर विश्वास करने वालों की संख्या सिर्फ 11 फीसदी दर्ज की गई है। सर्वे के रिजल्ट ग्लोबल मंच पर भारत की बढ़ती साख और प्रभाव को दर्शाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 46 फीसदी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक मानते हैं कि भारत वैश्विक मामलों में जिम्मेदारी के साथ रोल निभाएगा। इसके अलावा, 4 फीसदी लोगों ने भारत की लीडरशिप पर बहुत ज्यादा भरोसा जताया है।

भारत में सरकार की स्थिरता का फायदा

दुनिया भर में राजनीतिक अस्थिरता देखी गई। जहां भारत में नेतृत्व स्थिर रहा, वहीं पिछले एक दशक में दुनिया के अन्य बड़े लोकतांत्रिक देशों में कई बार नेतृत्व बदला है। यूनाइटेड किंगडम 2016 के बाद से अब तक वहां 5 प्रधानमंत्री (थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक और कीर स्टारमर) बदल चुके हैं। कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद पिछले 10 सालों में यूके को अपना छठा प्रधानमंत्री मिलने वाला है। साल 2016 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में तीन प्रधानमंत्री रहे हैं मैल्कम टर्नबुल, स्कॉट मॉरिसन और मौजूदा पीएम एंथनी अल्बानीज। इसी तरह 2014 में जब पीएम मोदी ने शपथ ली थी तब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, फिर जो बाइडेन आए, और 2024 में ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति चुनकर सत्ता में लौटे।

डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराध पर मोदी सख्त

समीक्षा बैठक में समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली, 24 जून (एजेंसी) : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे मामलों में सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वित, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी ने ये टिप्पणियां साइबर अपराध और 'डिजिटल अरेस्ट' के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा के दौरान कीं।

प्रधानमंत्री ने यह समीक्षा 'प्रगति' की 52वीं बैठक में की। मोदी ने कहा कि लोगों को एक विभाग या एजेंसी से दूसरे विभाग के चक्कर काटने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

4 परियोजनाओं की समीक्षा

मोदी ने चार राज्यों में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों से जुड़ी करीब 30,000 करोड़ रुपए की चार परियोजनाओं की भी समीक्षा की।

नीट पुनर्परीक्षा सुचारू रूप से कराने की पीएम ने प्रशंसा की

प्रधानमंत्री ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में, विभिन्न विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया और 'नीट-यूजी' पुनर्परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए किये गए प्रयासों की प्रशंसा की। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पूरे सरकारी तंत्र के मिलकर काम करने और विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल पर जोर दिया।

विकसित भारत के लिए एआइ का जिम्मेदारी के साथ उपयोग जरूरी

नई दिल्ली, 26 जून (भाषा)।

मोदी ने कहा कि कृत्रिम मेधा उद्योगों को नया स्वरूप दे रही है और उत्पादकता तथा नवाचार के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आइसीएआइ) की ओर से आयोजित 'एआइ इनोवेशन समिट' को भेजे अपने संदेश में मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण लेखांकन और वित्तीय पेशे में भी तेजी से बदलाव आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कृत्रिम मेधा (एआइ) को जिम्मेदारी के साथ और समावेशी तरीके से अपनाना भारत की विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को गति देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा उद्योगों को नया स्वरूप दे रही है और उत्पादकता तथा नवाचार के नए अवसर पैदा कर रही है।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आइसीएआइ) की ओर से आयोजित 'एआइ ... जाता है, तो ये कार्यकुशलता बढ़ा सकते हैं। साथ ही अनुपालन को मजबूत कर सकते हैं, ... राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कृत्रिम मेधा को जिम्मेदारी के साथ तथा

मन की बात में पीएम मोदी की अपील, गणेश प्रतिमा मिट्टी की ही लें, पीओपी वाली न खरीदें

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' में लोगों से अपील की कि इस बार गणेश प्रतिमा केवल मिट्टी से बनी ही खरीदें। पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) से बनी मूर्तियां न खरीदें। पीएम ने महाराष्ट्र के नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव का उदाहरण देते हुए बताया कि पेठकर परिवार ने घर में विवाह के मौके पर गांव के करीब साढ़े तीन हजार लोगों के लिए दुर्घटना बीमा कराया। हर व्यक्ति को 1

मेघालय के अद्भुत 'लिविंग रूट ब्रिज' की अनूठी विरासत

पीएम ने मेघालय के 'लिविंग रूट ब्रिज' का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ सालों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। ये समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। पीएम के मुताबिक, भारत ने रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हैरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है।

भास्कर नॉलेज पेड़ों की जड़ों से उगाए जाते हैं पुल

लिविंग रूट ब्रिज मजबूत पुल का रूप लेने में आमतौर पर 15 से 25 साल लेते हैं। इनकी उम्र करीब 500 साल आंकी जाती है। ये पुल अक्सर 50 से 100 फीट लंबे बनाए जाते हैं। मेघालय में ऐसे करीब 100 लिविंग रूट ब्रिज अलग-अलग गांवों में बताए जाते हैं। सबसे लंबा ब्रिज करीब 175 फीट

हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य : मोदी

सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि...प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया यात्रा का संदेश

हिंद महासागर एक सेतु

यूपीआई लागू करने समेत 19 करार

जल सुरक्षा के मजबूत प्रहरी...

समुद्री सामर्थ्य जिस देश का जितना मजबूत होगा, उसका आर्थिक-रणनीतिक प्रभाव, उतना ही सशक्त होगा। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को भारतीय नौसेना के 3 आधुनिक जहाज INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को कमीशन किया, जो 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित हैं। यह एक संतुलित और मिशन-तत्पर नौसेना के निर्माण की दिशा में भारत की बढ़ती क्षमता, मजबूत रक्षा निर्माण इकोसिस्टम और 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रति अटूट संकल्प का है प्रतीक...

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

आईएनएस दूनागिरी

- प्रोजेक्ट 17ए के तहत नीलगिरी श्रेणी का पांचवां युद्धपोत।
- सुपरसोनिक मिसाइलें, उन्नत वायु रक्षा प्रणाली और पनडुब्बी-रोधी हथियारों से लैस।
- इसकी हेलीकॉप्टर संचालन की क्षमता, निगरानी और मारक शक्ति को और बढ़ाती है।

आईएनएस संशोधक

- विशाल सर्वेक्षण पोत श्रेणी का चौथा जहाज।
- अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक एवं समुद्र-विज्ञान प्रणालियों से सुसज्जित।
- सटीक समुद्री सर्वेक्षण करता है। आवश्यकता पड़ने पर हॉस्पिटल शिप के रूप में उपयोग संभव।
- हेलीकॉप्टर संचालन की सुविधा ने इसकी बहुउद्देश्यीय क्षमता बढ़ाई है।

आईएनएस अग्रय

- भारतीय नौसेना का उथले जल में पनडुब्बी-रोधी युद्धपोत।
- एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी श्रृंखला का पांचवां जहाज।
- अत्याधुनिक सोनार, टॉरपीडो और पनडुब्बी-रोधी रॉकेट से लैस।
- वाटर जेट तकनीक के कारण तेज और चुस्त गति से कार्य करता है।

न्यू इंडिया समाचार पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 16-31 जुलाई, 2026

आरएनआई DELHIN/2020/78812 (प्रकाशन तिथि- 30 जून 2026, कुल पृष्ठ-48)

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक
कंचन प्रसाद
महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो,
सूचना भवन, द्वितीय तल,
नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित